

आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का नवजागरण

विष्णु देव साय सरकार ने गढ़ी छत्तीसगढ़ की नई पहचान

विरासत से विकास तक : जब संस्कृति बनी सुशासन की आधारशिला

शक्तिपीठों के विकास, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, लोककलाओं के संरक्षण,
संत परंपराओं का सम्मान और यात्रा सुविधाओं के विस्तार से छत्तीसगढ़ की
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मिली नई ऊर्जा

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

शक्तिपीठ परियोजना आस्था को जोड़ने वाला 1000 किलोमीटर का सर्किट



माँ दंतेश्वरी, माँ बम्लेश्वरी, माँ महामाया, माँ बागेश्वरी और माँ चंद्रहासिनी जैसे प्रमुख शक्तिस्थलों को जोड़ते हुए लगभग 1000 किलोमीटर का आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना श्रद्धा, संस्कृति और विकास का सुंदर संगम बनेगी।

मंदिरों का जीर्णोद्धार सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन



प्रदेशभर में प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है।

श्री रामलला दर्शन योजना श्रद्धालुओं को आस्था से जोड़ने का सेतु



अब तक लगभग 42 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 5 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिक देश के विभिन्न तीर्थस्थलों का लाभ ले चुके हैं। यह योजना आस्था और जनसेवा का प्रभावी माध्यम है।

महाकुंभ 2025 में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक सहभागिता



प्रयागराज में 4.5 एकड़ में बना छत्तीसगढ़ पैवेलियन 45 दिनों तक आस्था, संस्कृति और सेवा का केंद्र रहा। 50 हजार श्रद्धालुओं ने निःशुल्क आवास व भोजन की सुविधा का लाभ उठाया। राज्य की संस्कृति और पर्यटन की प्रदर्शनी ने देश-विदेश के आगंतुकों को आकर्षित किया।

“छत्तीसगढ़ प्रभु श्रीराम का ननिहाल, माता कौशल्या की जन्मभूमि और संत परंपराओं की पावन धरती है। हमारी सरकार आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शक्तिपीठ परियोजना, रामलला दर्शन योजना, मंदिरों के जीर्णोद्धार, लोक कलाकारों के प्रोत्साहन और धार्मिक पर्यटन के विकास के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हमारा विश्वास है कि कला समाज की आत्मा है और आस्था हमारी सबसे बड़ी शक्ति। विरासत के संरक्षण और जनसेवा के माध्यम से हम नए, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं।”

-विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

चिन्हारी योजना लोक संस्कृति संरक्षण का सशक्त माध्यम



लोक कलाकारों, शिल्पकारों, गायकों और नर्तकों का पंजीयन कर व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। चयनित कलाकारों को आर्थिक सहायता, मंचों पर प्रस्तुति के अवसर और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से नई पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026 कलाकारों को सम्मान व संबल



लोकनृत्य, लोकगायन, लोकनाट्य, वाद्ययंत्र, शिल्पकला, पारंपरिक पाककला सहित विभिन्न विधाओं के कलाकारों को प्रतिवर्ष 12 हजार से 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए विपश्यना अवकाश अनूठी पहल की शुरुआत



शासकीय कर्मचारियों में मानसिक तनाव दूर करने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विपश्यना (ध्यान) शिविरों में जाने के लिए विशेष सवेतन अवकाश की अनूठी पहल शुरू की गई है।

संत परंपरा और आध्यात्मिक विरासत को नया सम्मान कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा को मिली नई पहचान



दामखेड़ा का नाम अब कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा घोषित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न संत परंपरा केंद्रों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए योजनाबद्ध कार्य जारी है।

भोरमदेव से कौशल्या धाम तक धार्मिक पर्यटन का विस्तार



भोरमदेव सर्किट से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 148 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। माता कौशल्या मंदिर, शिवरीनारायण, दंडकारण्य क्षेत्र सहित अन्य स्थलों का विकास कर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जा रहा है।

गौ संवर्धन और धार्मिक संरक्षण सामाजिक समरसता की दिशा में कदम



गौधाम योजना के माध्यम से गौधामों में आवश्यक सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

नया छत्तीसगढ़: विकास और विरासत का संतुलित मॉडल



आस्था, संस्कृति, पर्यटन और विकास के समन्वय से छत्तीसगढ़ अपनी हजारों वर्षों पुरानी विरासत को सहेजते हुए एक समृद्ध, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत नहीं लिख रहा, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी भविष्य की मजबूत नींव भी तैयार कर रहा है।

मुख्य
उपलब्धियाँ



शक्तिपीठ सर्किट से
आध्यात्मिक पर्यटन
को नई शक्ति



हजारों श्रद्धालुओं
को तीर्थयात्रा
की सुविधाएँ



लोक कलाकारों
का सशक्तीकरण
और सम्मान



युवाओं को छात्रवृत्ति
से उज्ज्वल भविष्य



धार्मिक धरोहरों का
संरक्षण और संवर्धन

आस्था हमारी पहचान, संस्कृति हमारी शान, सेवा हमारा संकल्प

संक्षिप्त समाचार

जैतू साव मठ में श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई राधा अष्टमी



राधा अष्टमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना एवं धार्मिक आयोजन किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर राधानारी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। राधा अष्टमी के अवसर पर मठ में भगवान श्रीधाम-कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया। भजन-कीर्तन एवं धार्मिक कार्यक्रमों से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं ने राधानारी के जयकारों लगाए और प्रसाद ग्रहण किया। मठ के श्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज ने कहा कि – राधा अष्टमी के पर्व पर प्रतिवर्ष मठ में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष भी यहां परंपरागत रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें दो बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपस्थित हुए हैं भविष्य में भी यही सिलसिला निरंतर चलता रहे यही प्रभु से प्रार्थना है। ट्रस्ट कमेटी के सदस्य अजय तिवारी ने इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए लोगों के प्रति आभार जताया।

भाटापारा स्टेशन पर टिकट चेकिंग में 316 मामलों से 02,49,275 राजस्व प्राप्त

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ सुकरर विपुल विलासराव के निर्देश पर भाटापारा रेलवे स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान 17 सितंबर को चलाया गया। जिसमें भाटापारा स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, 14 ट्रेनों में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान में कुल 316 मामलों को दर्ज कर 2,49,275 रुपए राजस्व प्राप्त किया गया। किलाबंदी टिकट चेकिंग में बिना टिकट यात्रा करने वाले 202 यात्री पकड़े गए, जिससे 1,89,800 राजस्व प्राप्त हुआ। अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 71 यात्रियों से 50775 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ, अधिक लगेज लेकर यात्रा करने वाले 41 यात्रियों से 4700 रुपये, हुआ। अनाधिकृत वेंडर से 4000 रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। इस टिकट चेकिंग का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट लेने के प्रति जागरूक करना था। इस टिकट चेकिंग अभियान में सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद वाणिज्य निरीक्षक –2 एवं 25 टिकट चेकिंग स्टाफ, 4 आरपीएफ स्टाफ शामिल रहे। रेल प्रशासन यात्रियों को आगाह करता है कि वे यात्रा हेतु उचित टिकट एवं रेल परिसर मे प्रवेश करने के पहले प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य खरीदें। रेलगाड़ी एवं रेल परिसर को साफ सुथरा रखने में भी रेल प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान, प्रदेश में अब तक 996.5 मिमी बारिश

रायपुर। छत्तीसगढ़ इस बार के सीजन में मानसून मेहरबान रहा। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 19 सितंबर 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू मानसून सीजन में 1 जुन से अब तक प्रदेश में औसतन 9६.4 प्रतिशत (996.5 मिमी) बारिश हो चुकी है, जबकि इस अवधि के लिए राज्य की औसत वर्षा 1033.6 मिमी निर्धारित है। प्रदेशभर के जिलों में वर्षा का रुख मिश्रित रहा है। रेलगाड़ी सभागी को बात करें तो बलरामपुर जिले ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की है, जहां औसत वर्षा के मुकाबले 169.7% (1488.5 मिमी) पानी बरसा है। साथ ही सूरजपुर में 111.5% (1138.1 मिमी) और मनेन्द्रगढ़-चिमिरी-भरतपुर में 122.6% (1139.9 मिमी) वर्षा हुई है। हालांकि पड़ोसी जिले सरगुजा में केवल 77.3% (594.9 मिमी), जशपुर में 81.2% (805.1 मिमी) और कोरिया में 97.0% (892.8 मिमी) बारिश दर्ज की गई है। रायपुर सभाग में मानसून काफी मेहरबान नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर जिले में औसत का 126.9% (1०91.2 मिमी) पानी बरस चुका है। वहीं महासमुंद में 120.8% (1128.5 मिमी), गरियाबंद में 118.0% (1191.9 मिमी), बलौदाबाजार में 109.7% (1०07.1 मिमी) और धमतरी में 105.1% (1०61.0 मिमी) बारिश के साथ स्थिति काफी बेहतर बनी हुई है।

नन्हे हाथों ने रंगों से उकेरी स्वच्छ, हरित, शिक्षित और सशक्त भारत की तस्वीर

रायपुर। सेवा, जागरूकता और जनभागीदारी की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न विद्यालयों में चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और कला प्रतिभा के माध्यम से स्वच्छ, हरित, शिक्षित, सशक्त और विकसित भारत की परिकल्पना को रंगों में साकार किया। बच्चों ने अपनी कलाकृतियों के जरिए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। विद्यार्थियों की कलाकृतियों में स्वच्छ भारत, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, सबके लिए शिक्षा, उर्जा और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाएं, अक्षय वज्रां और विकासित भारत-2047 जैसे विषय प्रमुखता से उभरकर सामने आए। रंगों और संदेशों के माध्यम से बच्चों ने यह संदेश दिया कि स्वच्छता, शिक्षा, समानता, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के सामूहिक प्रयासों से आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार की जा सकती है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार, चिकित्सा जगत और समाज को मिलकर करने होंगे प्रयास

मुख्यमंत्री ने चौथे बीएमसी छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव-2026 का किया शुभारंभ, 200 से अधिक राष्ट्रीय और 11 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हो रहे शामिल

रायपुर। कैंसर के विरुद्ध लड़ाई केवल बीमारी के उपचार तक सीमित नहीं है। मरीज को आधुनिक और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने के साथ उसका मनोबल बनाए रखना तथा उसे यह विश्वास दिलाना भी उतना ही आवश्यक है कि इस कठिन लड़ाई में वह अकेला नहीं है। चिकित्सकों का संवेदनशील व्यवहार और परिवार एवं समाज का भावनात्मक सहयोग मरीज के भीतर बीमारी से लड़ने का हौसला बढ़ाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मेफेयर में बालको मेडिकल सेंटर द्वारा आयोजित चौथे बीएमसी छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव-2026 के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कैंसर आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। कैंसर का नाम सुनते ही मरीज के साथ पूरा परिवार चिंता और अनिश्चितता से घिर जाता है। बीमारी का प्रभाव केवल मरीज के शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी मानसिक, पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों पर भी पड़ता है। इसलिए कैंसर के उपचार में समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा

कि चिकित्सक जब आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ मरीज से जुड़ते हैं तो वे केवल बीमारी का उपचार नहीं करते, बल्कि मरीज और उसके परिवार के लिए विश्वास और हौसले का आधार भी बनते हैं। चिकित्सा विज्ञान में हो रही प्रगति के साथ मानवीय संवेदना का यह पक्ष कैंसर के विरुद्ध लड़ाई को और मजबूत बनाता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कैंसर से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बीमारी की समय पर पहचान है। शुरुआती अवस्था में कैंसर की पहचान होने पर प्रभावी उपचार की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैंसर सहित गंभीर बीमारियों की समय पर स्क्रीनिंग और रोकथाम को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री साय ने कॉन्क्लेव में उपस्थित विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे ऐसी आधुनिक तकनीकों, अनुसंधानों और प्रभावी उपायों पर विचार करें, जिनसे कैंसर की जल्द पहचान हो सके और उपचार को अधिक सस्ता, सुलभ तथा आम लोगों की पहुंच में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कॉन्क्लेव चिकित्सा जगत के अनुभव, शोध और नवाचार को साझा करने का महत्वपूर्ण



मंच हैं। यहां होने वाला विचार-विमर्श भविष्य की स्वास्थ्य नीतियों और उपचार पद्धतियों को नई दिशा देने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज था। आज शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर इनकी संख्या 15 हो गई है। इसके साथ ही पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन चिकित्सा संस्थानों में

झीरम हत्याकांड पर कांग्रेस ने लिए तीन बड़े फैसले

रायपुर। झीरम घाटी हत्याकांड मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज बैठक आयोजित कर तीन बड़े निर्णय लिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, इस मामले को लेकर कांग्रेस आलाकमान से समय लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे।



बैज ने कहा एनआईए कोर्ट के फैसले में नक्सल संगठन के निचले स्तर पर काम करने वाले और सूचना तंत्र के रूप में भूमिका निभाने वाले लोगों पर ही कार्रवाई हुई है। झीरम जैसे बड़े मामले में वास्तविक न्याय होना चाहिए, केवल कार्रवाई का दिखावा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस इस पूरे मामले में पीड़ित परिवारों और शहीद परिवारों से चर्चा की। बैठक

न्याय दिलाने के लिए हर संभव कानूनी रास्ते पर विचार किया जाएगा।

बैज ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही पार्टी के आलाकमान से

समय लेकर मुलाकात करेगी और एनआईए कोर्ट के फैसले को लेकर विस्तार से चर्चा करेगी। इसके अलावा दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस मुद्दे को उठाने की भी तैयारी है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित लोगों से चर्चा के बाद वरिष्ठ वकीलों से कानूनी राय ली जाएगी। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, ताकि झीरम घाटी के पीड़ित और शहीद परिवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा सके।

संगीत–कला से पीढ़ियों को जोड़ रहा चक्रधर समारोह: नेताम

कला साधना को किया नमन, कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित

रायपुर। 41वें चक्रधर समारोह की पांचवीं सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री एवं रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली को कामना की। इसके बाद महाराजा चक्रधर सिंह के छायाचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री नेताम ने कहा कि चक्रधर समारोह कला के माध्यम से लोगों को जोड़ने वाला ऐसा मंच है, जहां कला प्रेमी, कलाकार और कला सायक एक साथ आते हैं। उन्होंने रायगढ़ के उन कला प्रेमियों और श्रोताओं को नमन किया, जो पूरी रात बैठकर विभिन्न प्रस्तुतियों का आनंद



लेते हैं। उन्होंने कहा कि कला के प्रति रायगढ़ की यह निरंतर रुचि और समर्पण समारोह की विशेष पहचान है। प्रभारी मंत्री श्री नेताम ने कहा कि स्वर्गीय महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत और कला के माध्यम से रायगढ़ घराने की पहचान को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया। विशेष रूप से कथक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान ने रायगढ़ को देश और दुनिया में

अलग पहचान दिलाई। उनकी कला साधना से प्रेरित होकर चक्रधर समारोह आज भी कला की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में आयोजित यह

समारोह केवल प्रस्तुतियों का मंच नहीं है, बल्कि कला और संस्कृति की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। समारोह में प्रदेश के साथ देश के अलग-अलग क्षेत्रों से कलाकार शामिल होकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।

मंत्री श्री नेताम ने पांचवें दिन प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को स्मृति

चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कलाकारों को उनकी प्रस्तुतियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कलाकारों की साधना और कला प्रेमियों की सहभागिता से ही ऐसे आयोजन निरंतर आगे बढ़ते हैं। प्रभारी मंत्री ने कला प्रेमियों से समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाने और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, श्री अरुणधर दीवान, श्री श्रीकांत सोमावार, श्री सुभाष पाण्डेय, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह सहित जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी, कलाकार और बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित रहे।

अतुल सिंघानिया को 2026 का एएचपीआई उभरते हेल्थकेयर लीडर अवार्ड

रायपुर/जयपुर। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एएचपीआई) छत्तीसगढ़ चैप्टर के सचिव अतुल सिंघानिया को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनके नेतृत्व, व्यावसायिक योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एएचपीआई इमर्जिंग हेल्थकेयर लीडर अवॉर्ड 2026 से जयपुर में आयोजित एएचपीआई लीडरशिप समिट 2026 के समापन समारोह में श्री वी. श्रीनिवास आईआईएस, मुख्य सचिव राजस्थान शासन एवं डॉ. विनोद के. पॉल, पूर्व सदस्य, नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया।

एएचपीआई द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उभरते नेतृत्व को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे पेशेवरों के योगदान को पहचान देने की पहल है, जो अपनी संस्थागत जिम्मेदारियों के साथ-साथ व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

अतुल सिंघानिया पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से अस्पताल प्रबंधन



एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की वहीनयता एवं सुलभता, चिकित्सा शिक्षा एवं नीट, स्वास्थ्य बीमा तथा अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच संबंधों जैसे विषयों पर एएचपीआई के माध्यम से नीति-स्तरीय चर्चाओं और सुझावों में योगदान दिया है।

सम्मान प्राप्त करने के बाद अतुल सिंघानिया ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक, एक बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। एएचपीआई के राष्ट्रीय नेतृत्व सहित छत्तीसगढ़ चैप्टर अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एएचपीआई के साथ जुड़कर

उन्हें अस्पताल प्रबंधन की अपनी संस्थागत भूमिका से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था से जुड़े व्यापक विषयों पर काम करने और अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है।

उन्होंने श्री नारायणा हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. सुनील खेमका, डॉ. मेघा खेमका तथा पूरे श्री नारायणा हॉस्पिटल परिवार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान ने उनकी व्यावसायिक यात्रा को एक मजबूत आधार दिया है तथा उन्हें सीखने, आगे बढ़ने और स्वास्थ्य सेवा में योगदान देने के निरंतर अवसर प्रदान किए हैं।

एएचपीआई छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि अतुल सिंघानिया के योगदान और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। यह सम्मान उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में और व्यापक स्तर पर योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा।

झीरम फैसला : अरुण साव ने कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप

■ भूपेश बघेल का पलटवार, कहल- साव के परिवार के लोगों की नहीं हुई हत्या, उनको नहीं इसका अहसास



रायपुर। झीरम मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस नेताओं के बयानों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि साव के परिवार के लोगों की हत्या नहीं हुई है, इसलिए उनको इस चीज का एहसास नहीं हो सकता है।

झीरम मामले में कांग्रेस की बैठक पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला करते हुए कहा कि दावा ठोक-ठोक कर

कहते रहे कि झीरम का सच मेरी जेब में है, लेकिन जाँच के दौरान भी नहीं निकला। भूपेश बघेल मामले में केवल और केवल राजनीति करते रहे। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अपने बड़े नेताओं को खोया है। अरुण साव को केवल मजा आता है।

वहीं झीरम घाटी मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा पर संदेह को लेकर अरुण साव ने कहा कि एनआईए ने विस्तार से मामले की जाँच की है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साक्ष्य अंकित किए हैं। जाँच के

सेवा संकल्प अभियान में छात्राओं ने दिया अधिकार, कर्तव्य और जनभागीदारी का संदेश

रायपुर। सेवा, जागरूकता और जनभागीदारी की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, सूरजपुर में नुक़ड़ नाटक का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने प्रभावशाली अभिनय और सरल संवादों के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, सामाजिक सहभागिता तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

नुक़ड़ नाटक के माध्यम से छात्राओं ने बताया कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही संविधान नागरिकों को राष्ट्र और

समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने की प्रेरणा देता है।

छात्राओं ने संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को सहज एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हुए सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और सभी नागरिकों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया।

प्रस्तुति में छात्राओं ने मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देते हुए संविधान का सम्मान करने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।

रजिस्ट्री व स्टाम्प ड्यूटी में 50 फीसदी की छूट का दिखा असर, इसलिए जबर्दस्त रिस्पांश

■ आम लोगों के आशियाने का सपना पूरा करने का माध्यम बना क्रेडई प्रॉपर्टी एक्सपो

रायपुर। आम लोगों के आशियाने का सपना पूरा करने का सबसे बेहतर अवसर दे रहा है क्रेडई प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 एक माध्यम बनकर। एक्सपो में दूसरे दिन शनिवार को दोपहर से ही विजिटर्स इंडोर स्टेडियम पहुंचने लगे थे। इनमें से बहुतों ने अपने जरूरत की फ्लैट, बंगला, मकान, विला, प्लाट व कमर्शियल स्पेश की बुकिंग करायी। वे धन्यवाद करते रहे बिल्डर्स का क्योंकि इस बार एक्सपो में बुकिंग पर रजिस्ट्री व स्टाम्प ड्यूटी में 50 फीसदी की छूट दी जा रही है। इतने सारे प्रोजेक्ट के बीच उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है,अपने बजट व लोकेशन के हिसाब से बायर्स प्रापर्टी टटोलते रहे और बिल्डर्स



स्टाल पर हर जानकारी देने तैयार बैठे थे। ज्यादा संख्या में प्लाट,फ्लैट व स्वतंत्र मकान लेने वालों की रुचि दिखी। नए प्रोजेक्ट के प्रति भी उनका आकर्षण रहा जिसमें आधुनिक लाइफ स्टाइल की सारी सुविधा हो। बिल्डर्स के अलावा एक्सपो में बैंक, रेरा, टाइटल्स, पेंट्स, पाइप, सेनेटरी एसेसरीज, वायर, सोलर सिस्टम जैसे स्टाल भी लगे हैं। एक्सपो में पहुंचने वाले विजिटर्स इंट्री गेट पर अपनी जानकारी दर्ज करा रहे थे, शायद लकी ड्रा में उनका नंबर लग जाये। रविवार 20 सितंबर को प्रापर्टी एक्सपो का आखिरी दिन

है। रेरा के चेयरमैन श्री संजय शुक्ला एवं रेरा मेंबर्स श्री धनंजय देवांगन शनिवार को क्रेडई एक्सपो विजिट पर पहुंचे और आयोजन की प्रशंसा की। इस अवसर पर क्रेडई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। क्रेडई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पंकज लाहोटी, चेयरमेन मृणाल गोलखल, सचिव अभिषेक बछावत, प्रोग्राम चेयरमैन अशोक मूंदड़ा ने बताया कि पहले दिन उद्घाटन समारोह में पहुंचे अतिथियों ने एक्सपो आयोजन की सराहना करते हुए शासन व नगर निगम की ओर से हर संभव सहयोग की बात कही इसके लिए उनका आभार। हमारा ही मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आशियाने का सपना इस एक्सपो से पूरा हो सके। इसीलिए क्रेडई से संयुक्त 50 बिल्डर्स 250 से भी अधिक प्रोजेक्ट लेकर यहां मौजूद हैं।

कश्मीर पर पाकिस्तान की दोहरी नीति बेनकाब

कातिलाल मांडेत

भारतीय भूभाग पर फैसले का अधिकार किसी तीसरे देश को नहीं है। पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा संबंधी सहयोग को लेकर भारत ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग की पहली बैठक शुरू होने के बाद भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय क्षेत्रों से संबंधित पाकिस्तान और चीन के बीच किसी भी प्रकार का सीमा सहयोग भारत के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र पर अपने अवैध कब्जे को समाप्त करने की मांग भी दोहराई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार 16 सितंबर 2026 को दोनों देशों ने सीमा संयुक्त आयोग को औपचारिक रूप से सक्रिय किया। पाकिस्तान ने इसे सीमा प्रबंधन, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण, व्यापारिक आवाजाही और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। यानी पाकिस्तान इस तंत्र को चीन के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के साधन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत की आपत्ति का मूल कारण यही है कि पाकिस्तान और चीन के बीच प्रस्तावित सीमा सहयोग का संबंध उन क्षेत्रों से भी जुड़ता है जिन्हें भारत अपना संप्रभु भूभाग मानता है। भारत का कहना है कि किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में दो अन्य देश आपस में कोई व्यवस्था नहीं कर सकते जो भारत की संप्रभुता से संबंधित है। इसी आधार पर नई दिल्ली ने पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग को कानूनी आधार से रहित बताया है। भारत की आपत्ति का एक महत्वपूर्ण आधार 2 मार्च 1963 को हुआ तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता भी है। भारत सरकार लंबे समय से इसे अवैध और अमान्य मानती रही है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार भारत का कहना है कि इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र के शक्सगाम घाटी से संबंधित लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंपने की व्यवस्था की थी। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी। भारत का आधिकारिक रुख यह भी है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्रशासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों तथा चीन से जुड़े ऐसे किसी भी कदम को भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जोड़कर देखता है। यही वह बिंदु है जहां कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान की मूल स्थिति अलग दिखाई देती है। भारत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अपने संवैधानिक तथा संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान अपने आधिकारिक बयानों में जम्मू-कश्मीर को विवादित मुद्दा बताता रहा है। मई 2026 में चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में भी पाकिस्तान ने चीन को जम्मू-कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया और चीन ने इसे ऐतिहासिक रूप से लंबित विवाद बताते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा संबंधित प्रस्तावों के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान की बात कही थी। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की नीति को समझने के लिए उसके बयानों और गतिविधियों को अलग-अलग देखना जरूरी है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जम्मू-कश्मीर को विवादित मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करता है और इसके समाधान की मांग करता है। दूसरी ओर, वह चीन के साथ ऐसे सीमा और संपर्क संबंधी ढांचे को आगे बढ़ा रहा है जिनका संबंध भारत द्वारा अपने क्षेत्र के रूप में दावा किए जाने वाले इलाकों से भी जुड़ता है। यही स्थिति भारत की ओर से गंभीर आपत्ति का कारण बनती है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

4-बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद

गतांक से आगे...

परन्तु ध्यान देने से पता चलेगा, कि बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद इससे अधिक व्यापक और गम्भीर है। जब यह कहा जाता है, कि सर्व-मनात्मम् तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन, वह आत्मा से रहित है।

जड़ वस्तु के आत्मा से रहित होने का क्या अर्थ है? बौद्ध के अनुसार बाह्य जगत् में प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है, और कोई वस्तु स्थिर नहीं, अर्थात् किसी वस्तु में समय की दृष्टि से स्थिरता (कुछ देर तक रहना) नहीं हो सकता। इसी प्रकार देश की दृष्टि से भी कोई वस्तु फैली हुई (extended) नहीं, अर्थात् वह देश के एक बिन्दु पर रहने वाले कण या अवयव के रूप में है। कोई भी वस्तु देश के दो बिन्दुओं में रहने वाली, अर्थात् देश की दृष्टि से विस्तार-युक्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में अवयवों में रहने वाला कोई अवयवी या द्रव्य नहीं होता।

अतएव अनात्मवाद के सिद्धान्त (no-soul theory) का वास्तविक अर्थ है- अद्रव्य का सिद्धान्त (no-substance theory)। अद्रव्य सिद्धान्त का अर्थ यह है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती, जो समय की दृष्टि से (temporally) स्थिरता (duration) रखती हो, और देश की दृष्टि से (spatially) विस्तार (extention) रखती हो, यथार्थ तत्त्व (reality) समय की दृष्टि से लम्बाई में (vertically) सब ओर से कटी हुई है, और देश की दृष्टि से चौड़ाई में (horizontally) सब ओर से कटी हुई है। अर्थात् वह एक बिन्दुमय है, जिस के कोई अवयव नहीं, अथवा जिसमें अनेक अवयवों में रहने वाला कोई अवयवी और द्रव्य नहीं। कोई भी बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय, चाहे अन्य दृष्टियों से वे एक दूसरे के कितने भी विरुद्ध हों, स्थिर और विस्तारयुक्त द्रव्य को कदापि नहीं मानते।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

यूपीआई पर एमडीआर केंद्र सरकार की नई चुनौती

अजय बोकिल

यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) जैसी

भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय रियल टाइम (तत्काल) भुगतान प्रणाली पर भारत सरकार द्वारा लगाने वाले शुल्क पर मंचे बवाल और सियासत के बीच यह बात दब कर रह गई है कि सरकार जिसे ‘शुल्क’ बता रही है, वह वास्तव में एक ‘कर’ ही है। कहने को इसे व्यापारियों से वसूला जाना है, लेकिन यह बात समझने के लिए अर्थशास्त्री होना जरूरी नहीं है कि शुल्क का यह बोझ व्यापारी बड़ी चतुराई से आम लोगों पर शिफ्ट कर देंगे। और हमे शायद इसका पता भी न चले। आम लोगों को यह डर भी है कि यदि एमडीआर से सरकार को खासी कमाई होने लगी तो वह सभी यूपीआई पेमेंटों पर टैक्स लगा सकती है।

उधर नीट पेपर लीक और ई-20 पेट्रोल मामले में लीड लेने से चूकी कांग्रेस अब यूपीआई पेमेंट को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। उसे लग रहा है कि चूँकि यूपीआई पेमेंट का मुद्दा आम लोगों से जुड़ा है, इसलिए उसे इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके लिए मोदी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि अब तक ‘फ्री’ रहे यूपीआई पर एमडीआर अमेरिका के दबाव में लगाया गया है। उन्होंने इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। सपा नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ‘चुंगीजीवी’ हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपीआई पर सरकार के फैसले का बोझ आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा।

गौरतलब है कि देश में अब तक यूपीआई से पेमेंट पूरी तरह फ्री था। इसलिए इसका चलन लगातार बढ़ रहा था। आज देश में प्रतिदिन औसतन 66 करोड़ ट्रांजेक्शन यूपीआई के मार्फत होते हैं। करीब 55 करोड़ लोगों के पास कोई न कोई यूपीआई एप है। मोदी सरकार ने देश में नकदी की जगह डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरूआत 11 अप्रैल 2016 को की थी। यह सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि डिजीटल पेमेंट मामले में आज भारत दुनिया में नंबर वन है। अकेले पिछले महीने इसके जरिए 29.9 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ।

लेकिन लगता है सरकार अपनी ही इस सफलता में सुई चभोना चाहती है, जिसके पीछे कारण यूं तो डिजीटल पेमेंट सिस्टम को ज्यादा



मजबूत और प्रभावी बनाने का बताया जा रहा है। लेकिन आम नागरिक इसमें अपनी भुगतान स्वतंत्रता के हरण के संकेत बूझ रहा है। केन्द्र सरकार ने हाल में यूपीआई पेमेंट का नया फ्रेमवर्क जारी करते हुए कहा कि आगामी 15 अक्टूबर से इस पर 2000 रुपए से ज्यादा के सामान्य मर्चेट ट्रांजेक्शन पर 0.4 फीसदी एमडीआर देना होगा। इस एमडीआर की वसूली पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगेगा। बैंकिंग की भाषा में व्यक्ति से व्यक्ति को किए जाने वाले डिजीटल पेमेंट को ‘पीटूपी’ और व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले पेमेंट को ‘पीटूएम’ पेमेंट कहते हैं। यहां एमडीआर का अर्थ है ‘मर्चेट डिस्काउंट रेट।’ कहने को यह ‘छूट’ है, लेकिन भारत की जीरो एमडीआर और भारत सरकार का ‘रूपे नेटवर्क’ दोनो देशों के बीच बड़ी ‘व्यापार बाधा’ है। संक्षेप में कहें तो डोनाल्ड प्रशासन भारत में अमेरिकी कंपनियों के लिए डिजीटल पेमेंट्स का रास्ता ‘आसान’ बनाए जाने का हिमायती है।

जानकारों के मुताबिक यूपीआई भुगतान में मात्रा की दृष्टि से देखें तो जिस हिस्से पर एमडीआर लगेगा, वह 30 फीसदी ही है। इसकी अधिकतम सीमा 300 रू. है, जो सरकार की दृष्टि से अत्यंत ‘मामूली’ है। अलबता कुछ जरूरी सेवाओं के लिए एमडीआर के तहत 2 हजार रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 5 रुपए का फ्लैट एमडीआर लगेगा।

यह नियम रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल डीजल और खेती से जुड़े साजो सामान पर लागू होगा। एमडीआर आयद करने के पीछे सरकार का तर्क है कि देश में यूपीआई सिस्टम के संवातन और उसे बेहतर बनाने के मकसद से यह शुल्क आयद किया गया है। यह सुविचारित है और इसे किसी दबाव में वापस नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर संसद में कानून सरकार पहले ही पास करवा चुकी है। इस बीच यह मामला कोर्ट में भी

फूल सुगंध का हिसाब नहीं रखता, बस खिलता है



फिर भी वह खुशबू फैलाता रहता है।

एक गुलाब को गुलाब होने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। वह कमल बनने की भी कोशिश नहीं करता। प्रकृति ने हरेक को उसकी अपनी पहचान और संभावना दी है। लेकिन, मनुष्य ने इस सरल सत्य को भुला दिया है। हम दूसरे मनुष्यों को देखकर अपना जीवन निर्धारित करने लगते हैं। इसलिए, अपने जीवन को दूसरे के जैसा बनाने में मत खपाओ।

पहुंच गया है। दूसरी तरफ इस ‘शुल्क’ को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी हैं। मसलन शेयर ब्रोकर्स पर यह किस तरह से लागू होगा, क्वांकि वह अलग तरह का धंधा और भुगतान सिस्टम है।

भारत सरकार ने देश में यूपीआई को प्रमोट करने के लिए 2021-22 से प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इसके तहत ग्राहक से छोटे दुकानदार को होने वाले 2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर 0.15ब ईसेंटिव दिया जाता था। 2024-25 तक इस पर 8,276 करोड़ रू. का का ईसेंटिव दिया गया था। अब यह ईसेंटिव सरकार को महंगा पड़ने लगा है। शायद इसलिए भी सरकार पिछले दरवाजे से इसकी भरपाई करना चाहती है।

उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी दबाव का जो आरोप लगाया है, उसके पीछे वजह अमेरिका की शीर्ष वार्ताकार संस्था ‘यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव’ की इस साल आई रिपोर्ट है। इसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि अमेरिका की पेमेंट सेवा प्रदाता कंपनियां भारत के यूपीआई इकोसिस्टम में शामिल नहीं हो पा रही हैं। क्वांकि भारत की जीरो एमडीआर और भारत सरकार का ‘रूपे नेटवर्क’ दोनो देशों के बीच बड़ी ‘व्यापार बाधा’ है। संक्षेप में कहें तो डोनाल्ड प्रशासन भारत में अमेरिकी कंपनियों के लिए डिजीटल पेमेंट्स का रास्ता ‘आसान’ बनाए जाने का हिमायती है।

इस बीच सरकारी सूत्रों का दावा है कि देश में यूपीआई से होने वाला 96 फीसदी लेनदेन चूँकि दो हजार रुपए से कम का होता है, उस पर सरकार कोई शुल्क नहीं लगा रही है। सिर्फ बाकी के चार फीसदी लेनदेन पर शुल्क लगेगा, वह भी महज 0.40 फीसदी होगा। लेकिन जमीनी वास्तविकता यह है कि चार फीसदी लेनदेन का मौद्रिक मूल्य 66 फीसदी है। बाकी जो 96 फीसदी लेनदेन है उसका मौद्रिक मूल्य केवल 34 फीसदी है। आंकड़ों में समझें तो देश में कुल 314 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन में 207 लाख करोड़ का लेनदेन वो है, जो बाकी चार फीसदी के दायरे में है।

इसी से सरकार को कमाई होगी, जीएसटी से

मिलने वाली राशि अलग है। एमडीआर से मिली राशि सभी में बंटेगी। जिसमें आप के खाते वाली बैंक को 40 फीसदी, व्यापारी के बैंक को 30 फीसदी, यूपीआई एप्लीकेशन ऐप जैसे कि फोन पे, गूगल आदि को 20 प्रतिशत और बाकी का दस फीसदी हिस्सा अन्य प्रोसेसिंग एजेंसी को जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने अपना ‘भीम’ पेमेंट ऐप भी लांच किया है, लेकिन यूपीआई पेमेंट के बाजार में उसकी हिस्सेदारी 1 फीसदी से भी कम है। जबकि भारतीय यूपीआई बाजार में सबसे बड़ी खिलाड़ी अमेरिकी कंपनियां ‘फोन पे’ और ‘गूगल पे’ हैं।

बताया जाता है कि इन सभी कंपनियों और बैंकों की शिकायत है कि यूपीआई ‘फ्री’ होने से इस सेवा के संचालन में उन्हें घाटा उठाना पड़ता है। आरबीआई के डेटा विश्लेषण के आधार कुछ अर्थवेत्ताओं का मानना है कि यूपीआई मैनेज करने में करीब ढाई हजार से 8 हजार करोड़ तक खर्च आता है।

यह सही है कि तकनीकी तौर पर एमडीआर बड़े व्यापारिक भुगतान पर ही लगाया गया है। लेकिन पहले ही कर अपवंचन में माहिर व्यापारी यह शुल्क और जीएसटी अपनी जेब से क्वांकर देगा? वह इसे या तो आम उपभोक्ता की तरफ खिसकाएगा या फिर शुल्क से बचने नकद भुगतान के लिए कहेगा। ऐसी कोशिशें शुरू भी हो चुकी हैं। खासकर पेट्रोल पंपों जैसी जगहों पर तो 2 हजार से ऊपर का पेमेंट नकदी में मांगने लगे हैं। यह भी संभव है कि दुकानदार आप से 1900 रू. तक का भुगतान यूपीआई से और बाकी का नकद मांगे ताकि एमडीआर और जीएसटी से बचा जा सके। अगर वह शुल्क देगा भी तो इसकी वसूली वह आम उपभोक्ता की जेब से ही करेगा। यानी जेब आम आदमी की कटनी है।

सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि व्यापारी आम यूपीआई की वजह से आम उपभोक्ता का शोषण न करें, इसका मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है। अगर समय रहते इस एमडीआर को लेकर लोगों की आशंकाएं दूर न हुईं तो संभव है कि देश में नकदी भुगतान का युग फिर से लौट आए। वैसे भी रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि देश में यूपीआई की व्यापक लोकप्रिता के बावजूद नकदी का चलन कम नहीं हुआ है। उसे अभी भी उतने ही नोट छापने पड़ रहे हैं। एमडीआर के बाद क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।

हैं। मनुष्य भी तब सुंदर होता है, जब उसका कर्म उसके अहंकार की घोषणा नहीं, उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति बन जाता है। फूल की तरह खिलना शुरू करोगे। फूल कभी भी यह नहीं कहता कि जब मौसम मेरे अनुकूल होगा, तब ही खिलूंगा। वह तो बस खिलता रहता है। खिलना उसका स्वभाव है। अगर मनुष्य भी हमेशा अच्छे

इसलिए, हमेशा फूल की तरह खिलो और संभावनाओं को पहचानो। जब जीवन तुम्हारे सामने यह सवाल रखे कि तुमने क्या पाया, तो तुम कह सको कि मैंने अपने भीतर जो था, उसे पूरी तरह खिलने दिया। कोई पूछे कि तुम्हारी महक कितने लोगों तक पहुंची, तो मुस्कुराकर कहना कि मुझे नहीं मालूम। मैंने उसका हिसाब ही नहीं रखा। क्योंकि, फूल का धर्म सुगंध का हिसाब रखना नहीं, खिलना है।

हृतियों से सीधे भिड़ने से पीछे हटे अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान

नीरज कुमार दुवे

हृतियों के हमले से परेशान सऊदी अरब ने मदद के लिए पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पाकिस्तान ने सीधे यमन के युद्धक्षेत्र में उतरने से दूरी बनाए रखी। सऊदी अरब ने फिर अमेरिका से सैन्य मदद मांगी, मगर वाशिंगटन ने भी हृतियों के खिलाफ सीधे हमले से इंकार कर दिया। इसके बाद रियाद ने उस इजराइल की ओर भी रुख किया, जिसके साथ उसके औपचारिक राजनयिक संबंध तक नहीं हैं। वहां से खुफिया और सुरक्षा सहयोग मिला, लेकिन वह भी सऊदी अरब की जरूरत के मुताबिक निर्णायक सैन्य समर्थन साबित नहीं हुआ। आखिरकार रियाद को चीन की ओर देखना पड़ा और यहीं से पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन की तस्वीर अचानक बदलती दिखाई दी। चीन ने सीधे हृतियों पर हमला करने की बजाय उनके सबसे महत्वपूर्ण समर्थक ईरान पर दबाव डालने का रास्ता चुना है।

हम आपको याद दिला दें कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने अगस्त में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते में किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना गया है और सामूहिक प्रतिरोध तथा रक्षा सहयोग मजबूत करने की बात कही गई है। लेकिन हृतियों के खिलाफ यमन में सीधे सैन्य अभियान के सवाल पर पाकिस्तान ने पलटौ मार ली। यानी काजग पर सामूहिक सुरक्षा की भाषा जितनी मजबूत है, युद्ध के मैदान में उसकी व्यावहारिक सीमा उतनी ही स्पष्ट दिखाई दे रही है।

वहीं सऊदी अरब की अगली उम्मीद अमेरिका से थी। रियाद ने सीधे अमेरिकी सैन्य समर्थन की मांग की, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हृतियों के खिलाफ सऊदी अभियान में सीधे अमेरिकी हमलों की मंजूरी नहीं दी। वाशिंगटन ने खुफिया और तक्ष्य संबंधी सहयोग तक अपनी भूमिका सीमित रखी। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सात दशकों से ज्यादा पुराना सुरक्षा-सहयोग ढांचा है। वर्ष 1951 के पारस्परिक



रक्षा सहायता समझौते से शुरू हुआ यह रिश्ता बाद में हथियारों की आपूर्ति, सैन्य प्रशिक्षण, वायु और मिसाइल रक्षा तथा व्यापक सुरक्षा सहयोग में बदल गया। अमेरिका खुद सऊदी अरब को दायकों से क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदार और अपने सबसे बड़े रक्षा उपकरण खरीदारों में एक बताता रहा है।

यही वजह है कि आज सऊदी अरब को हृतियों के हमलों के बीच अकेले जुझते देख उ न तमाम देशों में भी बेचैनी पैदा हो गयी है, जिन्होंने लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर भरोसा करते हुए अपनी स्वतंत्र सैन्य क्षमता को उसी अनुपात में विकसित नहीं किया। खाड़ी और पश्चिम एशिया के वे देश, जो अमेरिकी सुरक्षा साझेदारी को बाहरी खतरों से बचाव की महत्वपूर्ण गारंटी मानते रहे हैं, अब यह सवाल पूछने पर मजबूर हैं कि संकट की घड़ी में अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धता की वास्तविक सीमा आखिर कितनी है। सऊदी अरब के मामले ने इस बहस को और तीखा कर दिया है। देखा जाये तो यदि इतना पुराना और गहरा सुरक्षा साझेदार भी सीधे सैन्य समर्थन के लिए वाशिंगटन की ओर देखता रह जाए, तो अमेरिकी सुरक्षा आक्षासनों पर निर्भर दूसरे देशों के रणनीतिक गणित पर इसका असर पड़ना तय है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे असहज करने वाला पहलू यह है कि वाशिंगटन ने अपने लिए सुरक्षा का रास्ता निकालने में हृतियों से गोपनीय बातचीत करने की सलाह नहीं किया। योमन की राजधानी मस्कट में अमेरिकी अधिकारियों और हूती प्रतिनिधियों के बीच गुप्त बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार हृतियों ने अमेरिकी जहाजों को निशाना नहीं बनाने

और वर्ष 2025 के युद्धविराम के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आश्वासन दिया। इसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए सीधे युद्ध में उतरने से दूरी बनाए रखी।

इस घटनाक्रम ने सऊदी अरब के सामने एक बेहद कठोर रणनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस अमेरिका के साथ उसने दशकों तक सुरक्षा साझेदारी बनाई, उसी अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए हृतियों से संवाद का रास्ता खोल लिया, लेकिन सऊदी अरब की तत्काल सैन्य सहायता की मांग पर प्रत्यक्ष युद्ध में उतरने से इंकार कर दिया। यही वह कारण है जहां अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर भरोसा करने वाले दूसरे देशों की चिंताएं भी गहरी होती हैं।

इसके अलावा, जब पारंपरिक सहयोगियों से अपेक्षित सैन्य समर्थन नहीं मिला तो सऊदी अरब ने अप्रत्याशित कदम उठाया। अमेरिकी मध्य कमान के माध्यम से सऊदी अरब और इजराइल के बीच संपर्क स्थापित हुआ। इजराइल से मुख्य रूप से हृतियों की सैन्य तैनाती, संभावित हमलों और महत्वपूर्ण ठिकानों से संबंधित खुफिया सहायता पर चर्चा हुई। इजराइली पक्ष से सऊदी बुनियादी ढांचे और रणनीतिक ठिकानों की रक्षा के लिए खुफिया तथा वायु रक्षा क्षमताओं से संबंधित सहायता की संभावना भी सामने आई है। लेकिन यह सहायता प्रत्यक्ष इजराइली सैन्य हस्तक्षेप में नहीं बदली। यानी रियाद को यहां भी वह सैन्य समर्थन नहीं मिला जिसकी उसे हृतियों की तेजी से बढ़ती पकड़ के सामने जरूरत है।

यहीं फकीर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। हृतियों ने लाल सागर के तट और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास तेजी से बढ़त बनाई है। यह सऊदी तेल निर्यात और समुद्री परिवहन के लिए गंभीर खतरा है। इसी पृष्ठभूमि में सऊदी अरब ने चीन से हस्तक्षेप की अपील की। चीन ने सार्वजनिक रूप से संयम, बातचीत और सुरक्षित नौवहन की बहाली की मांग की, लेकिन पर्दे के पीछे उसका संदेश कहीं ज्यादा सीधा था। चीन ने तेहरान से कहा है कि वह हृतियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और उन्हें नियंत्रित करे, ताकि संघर्ष लाल सागर तथा ऊर्जा

मार्गों में और न फैले। चीन ने हृतियों को रोकने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत यानि आर्थिक और कूटनीतिक पकड़ का इस्तेमाल किया है।

हम आपको बता दें कि चीन एक दशक से अधिक समय से ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ईरानी तेल का सबसे महत्वपूर्ण खरीदार भी है। 2025 में ईरान के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल निर्यात का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा चीन ने खरीदा था। यही आर्थिक रिश्ता बीजिंग को तेहरान पर प्रभाव डालने की क्षमता देता है। इसके अलावा 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध बहाल कराने में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई थी। इसलिए बीजिंग के पास दोनों पक्षों से संवाद का वह चैनल मौजूद है जो अमेरिका के पास नहीं है।

देखा जाये तो इस पूरे संकट का सबसे बड़ा सामरिक पहलू केवल सऊदी अरब की सुरक्षा नहीं है। मामला दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार की सुरक्षा तक पहुंच चुका है। एक तरफ होरमुज जलडमरूमध्य पर तनाव है और दूसरी तरफ हृतियों की बढ़ती पकड़ बाब-अल-मंदेब पर दबाव बना रही है। यदि दोनों प्रमुख समुद्री मार्ग लंबे समय तक बाधित होते हैं तो तेल, गैस और वैश्विक समुद्री व्यापार पर एक साथ दबाव पड़ सकता है। यही चीन की सबसे बड़ी चिंता है। चीन की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयात पर निर्भर है और खाड़ी क्षेत्र उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए बीजिंग के लिए हूती संकट अब केवल सऊदी अरब या यमन का मामला नहीं रहा।

बहरहाल, सऊदी अरब के सामने अब केवल हृतियों की चुनौती नहीं है, बल्कि उसके पारंपरिक सुरक्षा साझेदारों की सीमाएं भी उजागर हो गई हैं। पाकिस्तान समझौते की भाषा तक सीमित है, अमेरिका प्रत्यक्ष युद्ध से पीछे है, इजराइल की मदद फिलहाल खुफिया और रक्षा सहयोग तक सीमित है और चीन पहली बार इस संकट में निर्णायक मध्यस्थ की भूमिका आजमा रहा है।

आज का इतिहास

- 1831 भाप से चलने वाली पहली बस बनाई गयी। 30 लोगों की क्षमता तथा अत्यंत धीमी गति से चलने वाली इस बस के आविष्कारक गोर्डन ब्राउन थे जिनका संबंध ब्रिटेन से था।
- 1839 नीदरलैंड (एम्स्टर्डम-हारलेम) में पहला रेल रोड खुला।
- 1854 अलमा का युद्धः क्रीमियाई युद्ध की पहली बड़ी लड़ाई में ब्रिटेन और फ्रांस के गठबंधन ने रूस को पराजित किया।
- 1856 भारत के महान संत एवं समाज सुधारक श्री नारायण गुरु का जन्म हुआ।
- 1857 ऑगम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने आत्मसमर्पण किया। कैदी बनाकर लाल किले लाए गए।
- 1857 ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोहियों से दिल्ली को मुक्त कराकर फिर उस पर कब्जा किया।
- 1878 मद्रास का अखबार द हिंदू पहली बार जी.एस.एस अय्यर के संपादन में सप्ताहिकी के रूप में प्रकाशित।
- 1946 पहला कांस फिल्म समारोह आयोजित।
- 1970 रूसी प्रोब ने चांद की सतह से कुछ चट्टानें इकट्ठा की।
- 1973 दुनिया के मशहूर 'बैटल ऑफ सक्सेस' में बिली जीन किंग ने जीत दर्ज की।
- 1983 एप्पल उपग्रह ने कार्य करना बंद किया।
- 1984 लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित अमेरिकी दूतावास पर आत्मघाती हमला किया था।
- 1995 संयुक्त राज्य महासभा का 50वां अधिवेशन प्रारम्भ।
- 1999 तमिल सिनेमा की स्वप्न सुदुरी के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री राजकुमारी का निधन। उनकी फिल्म हरिदास 114 सप्ताह तक चेन्नई के सिनेमाघर में चली थी।
- 2000 क्लिंटन दम्पति 'व्हाइट वाटर कांड' के आरोपों से मुक्त।
- 2001 अमेरिका ने 150 लड़ाकू विमान खाड़ी में उतारे।
- 2003 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस्त्रायल से यासिर अरफात की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।
- 2006 ब्रिटेन के रॉयल बॉटैनिक गार्डन्स के वैज्ञानिकों को 200 वर्ष पुराने बीज उगाने में कामयाबी मिली।
- 2009 मराठी फिल्म 'हरिशचन्द्राची फैक्ट्री' को आस्कर अवार्ड्स की विदेशी फ़िल्म कैटेगरी में भारत की एंट्री के तौर पर चुना गया।
- 2018 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और विश्व चैंपियन भारोत्तोलक मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा।
- 2021 भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन।
- 2021 चरणजीत सिंह चत्री पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर बढ़ाई भारत की प्रतिष्ठा और मान-सम्मान

डॉ. मोहन यादव

यशस्वी नरेन्द्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में ढाई दशक की गौरवपूर्ण यात्रा पर विशेष राजनीति के मैदान में ऐसे अनेक नेता और जननेता हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इनमें कुछ अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने गए, तो कुछ ने अपने राजनीतिक कौशल से अलग पहचान बनाई। लेकिन ऐसे नेता विरले ही होते हैं, जो संगठन से निकलकर मुख्यमंत्री के रूप में अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यकुशलता की मिसाल कायम करें और आगे चलकर प्रधानमंत्री के रूप में न केवल देश की राजनीति और शासन-व्यवस्था को नई दिशा दें, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाये।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सार्वजनिक जीवन ऐसी ही असधारण यात्रा का उदाहरण है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 13 वर्षों तक उन्होंने शासन की एक ऐसी शैली विकसित की, जिसमें विकास, सुशासन और जनभागीदारी को केंद्र में रखा गया। इसके बाद वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के बाद उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और विश्व में प्रभावशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे परिस्थितियों को केवल देखते नहीं, बल्कि उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। दुनिया की राजनीति में कहाँ मौन रहना है, कहाँ अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी है और कहाँ दृढ़ता के साथ भारत के हितों की रक्षा करनी है। इसका संतुलन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी विदेश नीति में लगातार

प्रदर्शित किया है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने विश्व के विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है।

आज भारत विश्व राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना हो, पश्चिम एशिया में भारत के हितों की रक्षा करनी हो या रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे जटिल अंतरराष्ट्रीय विषयों पर शांति और संवाद का पक्ष रखना हो, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय दृष्टिकोण को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि संकट के समय भारत ने केवल अपने नागरिकों की ही चिंता नहीं की, बल्कि मानवता के प्रति अपने दायित्व को भी निभाया। कोरोना महामारी के कठिन दौर में भारत ने जिस प्रकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और जरूरतों का ध्यान रखा, वह अभूतपूर्व था। इसके साथ ही भारत ने अनेक देशों को दवाइयों, वैकसीन और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से लेकर तुर्किए तक, जब भी आवश्यकता पड़ी, भारत ने सहायता का हाथ बढ़ाया।

युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चलाए गए। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी हो या संकटग्रस्त परिस्थितियों में अन्य भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाना इन प्रयासों ने यह संदेश दिया कि भारत अपने प्रत्येक नागरिक की



सुरक्षित उनके देश वापस पहुँचाने के प्रयास किए गए। यह भारतीय संस्कृति की उस भावना का परिचायक है, जिसमें मानवता को सर्वोपरि माना गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को सहन करने वाला देश नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संकल्प को दुनिया के सामने दृढ़ता से रखा। भारत ने यह स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई उसके लिए केवल सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न भी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद को लेकर भारत की नीति में जो दृढ़ता आई है, उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान आकर्षित किया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे को वैश्विक मंचों पर प्रभावी ढंग से उठाने और आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत की मानवीय संवेदनशीलता का परिचय उस समय भी मिला, जब कठिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान के विद्यार्थियों को भी सुरक्षा के साथ वापस पहुँचाने के प्रयास किए गए। यह भारतीय संस्कृति की उस भावना का परिचायक है, जिसमें मानवता को सर्वोपरि माना गया है। हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से भारत ने वैश्विक मंच पर स्वयं को एक संतुलित, व्यवहारिक और नीतिगत रूप से स्वायत्त राष्ट्र के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। भारत की साथ एक ऐसे देश के रूप में बनी है जो वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और पश्चिमी देशों तथा पूर्वी शक्तियों के बीच संवाद का संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ब्रिक्स किसी पश्चिम-विरोधी गुट के रूप में नहीं, बल्कि एक समावेशी और सुधारात्मक बहुपक्षीय मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास और आतंकवाद के प्रति कड़े रुख ने वैश्विक स्तर पर देश की विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाया है।इस पूरे परिदृश्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका अत्यंत निर्णायक और प्रभावी रही है। सम्मेलनों के दौरान विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ की गई उनकी द्विपक्षीय बैठकों ने न केवल जटिल क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने में मदद की, बल्कि भारत के आर्थिक और व्यापारिक हितों को भी नई दिशा दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष गरीब और वंचित वर्ग के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। जनकल्याण की योजनाओं में जाति, क्षेत्र या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, उच्चला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों परिवारों

तक पहुँचा है। गरीबों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। पक्का घर, शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, बैंक खाता, स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्यान्न की उपलब्धता जैसे विषयों को जनकल्याण की मुख्यधारा में लाया गया।

आयुष्मान भारत योजना ने गरीब और असहाय परिवारों के लिए गंभीर बीमारियों के उपचार को आर्थिक रूप से अधिक सुलभ बनाया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जी के लिए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ केवल नारा नहीं, बल्कि शासन का मूल मंत्र रहा है।

प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालते ही मोदी जी ने स्वच्छता को राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया। उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दिया और देशवासियों से स्वच्छ भारत के निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया। इस अभियान ने देश की सोच में परिवर्तन लाने का काम किया। गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता जनआंदोलन बनी। मध्यप्रदेश ने भी इस अभियान में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इंदौर का लगातार स्वच्छ शहरों में अग्रणी रहना इस जनभागीदारी का प्रेरक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बना चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

दिशा सालियान केस : बार–बार राजनीतिक ‘दिशा’ ढूंढने का प्रयास

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र की राजनीति में ‘सेलिब्रिटी मैनेजर’ दिशा सालियान की मौत के मामले को एक बार फिर हवा मिल गई है। लगभग सवा छह साल बाद सुर्खियों में आने प्रकरण में बीते दो सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया है। दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर अदालत ने सीबीआई को एक वरिष्ठ और अनुभवी जांच अधिकारी नियुक्त करने, सतीश सालियान का बयान दर्ज करने और उसके आधार पर प्राथमिकी(एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया है। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच में पर्याप्त आधार मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। आदेशानुसार अब जांच सीबीआई की दिल्ली स्पेशल क्राइम यूनिट में पुलिस अधीक्षक सीमा पाहूजा की निगरानी में आ चुकी है। उनका नाम हाथरस, उनाव, हिमाचल प्रदेश के गुड़िया मामले और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले जैसी चर्चित जांचों से जुड़ा रहा है। कार्रवाई आगे बढ़ते हुए 50 से अधिक लोगों के नामों तक पहुंच गई है, जिसमें अनेक चर्चित नाम हैं। अदालत के आदेश के बावजूद कुछ नामों को उछालकर राजनीति आरंभ हो चुकी है। ध्यान देने योग्य यह भी है कि मामले से जुड़ी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की घटना पर सीबीआई अपनी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दे चुकी है। बताया जाता है कि 8 और 9 जून 2020 की दरमियानी रात में मुंबई के मलाड इलाके में स्थित रीजेंट गैलेक्सी सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर दिशा अपने स्मॉल्ट रोहन रॉय के घर पर थीं। जहां चार अन्य दोस्त भी मौजूद थे। देर रात दिशा घर

की खिड़की से नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने पार्टी में मौजूद लोगों और दिशा के परिवार के सदस्यों से पूछताड़ की, जिसमें किसी ने किसी व्यक्ति पर संदेह नहीं बताया। पुलिस ने उस समय कहा था कि दिशा अपने किसी काम को लेकर परेशान थीं और जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होना संभव था। मामले में संदेह उस समय पैदा किया गया, जब दिशा की मौत के छह दिन बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई। दिशा कुछ समय सुशांत की मैनेजर थीं। यहीं से सोशल मीडिया पर दोनों मौतों को जोड़ा गया और कई तरह के दावे किए गए। दिशा के पिता भी दोनों घटनाओं के बीच संबंध की बात कहते आए। उनका दावा है कि दिशा के पास कुछ ऐसी जानकारी थी, जिसे उन्होंने सुशांत के साथ साझा किया था। इससे दोनों मामलों को जोड़कर देखा जाना चाहिए। वह अपनी बात पर अडिग रहते हुए उच्च न्यायालय तक पहुंचे जहां उन्हें दोबारा जांच का आदेश मिला। हालांकि सुशांत की मौत के मामले में किया गया दावा जांच में साबित नहीं हुआ। सीबीआई ने मार्च 2025 में अपनी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ में मौत में किसी साजिश या ‘फाउल प्ले’ के सबूत नहीं मिलने का दावा किया। जिससे यह साफ है कि मामले का आधा भाग पहले ही सीबीआई की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ में सामने है। शुरुआत में दिशा की मौत की कहानी सीमित दायरे में सिमटी थी। कोई अधिक कहने के लिए तैयार नहीं था। मगर सोशल मीडिया ने उसे एक अलग दिशा देकर उलझा दिया। जिसमें एक रात की पार्टी सामने आई। जिसमें कई प्रभावशाली लोग बताए गए। वहां दिशा की यौन अत्याचार के बाद हत्या कर लाश नीचे फेंकने की ‘थ्योरी’ समझाई गई।

मृत्युंजय दीक्षित

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की 10 वर्षों की गौरवमयी यात्रा और अभूतपूर्व सफलता के बाद केंद्र सरकार ने आगामी 15 अक्टूबर 2026 से इसके माध्यम से दो हजार रुपए से अधिक के कारोबारी भुगतान पर कारोबारियों के लिए 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने का निर्णय लिया है।

झूठ की गूँज एक्सप्रेस चलाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन इस निर्णय के लिए सरकार पर अमेरिकी दबाव में झुकने, घुटने टेकने जैसे आरोप लगा रहा है। विपक्ष सोशल मीडिया पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क को मोदी टैक्स बताकर इसे तत्काल वापस लेने की मांग कर रहा है। 2000 से ऊपर के कारोबारी भुगतान के इस 0.4 प्रतिशत शुल्क पर विपक्ष के झूठ की गूँज सोशल मीडिया से लेकर व्यापारियों तक पहुंच चुकी है। राजधानी लखनऊ व उत्तर प्रदेश के व्यापारी इसका प्रबल विरोध कर रहे हैं जबकि पेट्रोल पंप कंपनियां इस टैक्स को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रही हैं, कुछ पेट्रोल पंपों ने यूपीआई से करें भुगतान वाले बैनर व पोस्टर हटाने भी शुरू कर दिए हैं।

राहुल गांधी व उनका ईको सिस्टम एक सुनियोजित साजिश के तहत सोशल मीडिया पर तरह – तरह की अफवाहें फैला रहा है कि अब डिजिटल लेन-देन कम हो जाएंगे और बाजार में कैश का चलन बढ़ जाएगा। जो लोग कैश की जगह यूपीआई पेमेंट करते हैं उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना होगा। राहुल गांधी व इंडी गठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि 0.4प्रतिशत शुल्क की आड़ में वो



अपनी राजनीति को चमका लेंगे और मोदी सरकार को छवि को गहरा आघात लगा देंगे। राहुल गांधी ऐसे प्रयास पहले ही कर चुके हैं। राफेल से लेकर कोविड तक और फिर अमेरिका –ईरान युद्ध के मध्य गैस व तेल का संकट पैदा होने पर भी इन लोगों ने सोचा था कि अब तो मोदी सरकार चली ही जाएगी।

आश्चर्यजनक बात ये है कि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी 0.4प्रतिशत एमडीआर पर मोदी सरकार को घेरे हैं वहीं संसदीय समिति में शामिल कांग्रेस के सांसदों ने इसका समर्थन किया है। सरकार का विरोध करने से पहले राहुल गाँधी को अपने उन सांसदों से बात करनी चाहिए थी जिन्होंने वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति में यूपीआई पर यह टैक्स लगाने का समर्थन किया था। इस समिति में कांग्रेस सांसद तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, गौरव गोरोई, किशोरीलाल और के. गोपीनाथ जैसे नेता शामिल थे।

यूपीआई भारत का सफलतम डिजिटल नवाचार है। आज देश का लगभग हर नागरिक डिजिटल भुगतान कर रहा है। आम जनता अपनी जेब में नोट व खुले पैसे रखना भूल चुकी है। यूपीआई से प्रतिदिन 79 करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफार्म बन चुका है जिस पर

विगत वर्ष 24 हजार करोड़ ट्रांजेक्शन के माध्यम से 314 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ। इतना बड़ा प्लेटफार्म अभी तक पूरी तरह से नि: शुल्क चल रहा था। एक वर्ष में डिजिटल प्लेटफार्म को चलाने में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं और सरकार ने इसे 10 वर्ष तक नि:शुल्क चलाया। लेन-देन की संख्या अरबों में पहुंचने के बाद सर्वर ,साइबर सुरक्षा और तकनीकी रख रखाव के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल की जरूरत है। अब चूँकि नियम साफ हो चुके हैं और बड़े मर्चेंट लेन देन पर शुल्क का रास्ता खुल गया है इससे उन बैंकों और फिनेटेक कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधरेगी जो इस नेटवर्क को चला रह हैं।सरकार का यह निर्णय आते ही फिनेटेक कंपनियों की शिकायत भी कर सकता है। विकसित भारत विरोधी अराजक तत्व अभियान चलाकर, सामान्य जनता की बहका रहे हैं जबकि सत्यता यह है कि 96 प्रतिशत यूपीआई भुगतान अभी भी एमडीआर से बाहर है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम एकदम स्पष्ट हैं जिसके अनुसार रेहड़ी पटरी लगाने वालों तथा फल सब्जी आदि बेचने वाले किसी भी छोटे कारोबारी की अतिरिक्त शुल्क कहीं नहीं देना है। प्रतिमाह एक लाख रूपए का

कारोबार करने वाले दुकानदार को भी कोई चार्ज नहीं देना है। उपभोक्ता जब कारोबारी को यूपीआई के माध्यम से दो हजार रुपए का भुगतान करेगे तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह शुल्क केवल कारोबारियों पर लगेगा। कारोबारियों से स्पष्ट कहा गया है कि वह शुल्क की वसूली वह ग्राहकों से नहीं कर सकते। नियमों के अनुसार किसी भी कारोबारी को 2000 रुपए तक पेमेंट एमडीआर से छूट वाला ही रहेगा इसलिए किराना, दवाएं ,रेस्तरां, कैब ,छोटी खरीदारी और रोजमर्रा के अधिकांश भुगतान पर कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा इंधन और कृषि इनपुट जैसी जरूरी या कम मुनाफे वाले क्षेत्रों को अलग राहत दी गई है।

विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि इस एमडीआर शुल्क से यूपीआई से भुगतान का अनुभव पहले जैसा ही रहेगा अपितु यह और आसान हो जाएगा। ग्राहक के लिए यूपीआई पूरी तरह से नि:शुल्क है छोटे भुगतान और व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं केवल 2,000 रुपए से ऊपर के चुनिंदा बड़े कारोबारियों पर 15 अक्टूबर 2026 से सीमित एमडीआर लागू होगा।

विपक्ष के झूठ की गूँज कितनी भी तेज हो भारत की आम जनता अब समझदार हो गई है और बेधड़क यूपीआई का प्रयोग करती रहेगी। राहुल गांधी एंड कंपनी को पहले इस बात का उत्तर देना होगा कि यदि उनको एमडीआर से विरोध था तो उनके सांसदों ने अवसर दिए जाने पर भी इसका विरोध क्यों नहीं किया और क्यों हंगामा कर रहे हैं? स्थापित कल्याण रूप से राहुल गाँधी की नीयत में खोत है।

बसपा से निकलते ही आकाश के लिए लग गयी पार्टियों की कतार

नीरज कुमार दुबे

बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए शायद यह सोचा होगा कि उन्होंने आकाश आनंद की राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी, लेकिन बसपा से बाहर निकलते ही तस्वीर बदल गई। उत्तर प्रदेश का पूरा राजनीतिक वर्ग बाँहें फैलाकर आकाश आनंद का इंतजार करता दिखाई दे रहा है। सत्तापक्ष एनडीए के सहयोगी दलों से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन आंदोलन की राजनीति करने वाले नेताओं तक, हर कोई आकाश आनंद को अपने पहले में लाने की कोशिश में जुट गया है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई यह कवायद बताती है कि निशाना भले ही आकाश आनंद हों, लेकिन असली नजर उस बहुजन सामाजिक आधार पर है, जिसे बसपा ने दशकों में तैयार किया है। मायावती भले ही चुनावी गठजोड़ से लगातार दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन आकाश के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन वोट की नई गोलबंदी की संभावनाएं तलाशने का खेल शुरू हो चुका है।

सबसे पहले निषाद पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी संजय निषाद ने आकाश आनंद को खुला न्योता दिया। उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर और काशीराम से जुड़े बहुजन आंदोलन के पुपुने नारे का हवाला देते हुए आकाश से आगे आने और अपनी टीम के साथ मुख्यालय में शामिल होकर काशीराम के सपने को पूरा करने की अपील की। यानी मामला महज एक नेता को पार्टी में शामिल करने का नहीं, बल्कि बहुजन राजनीति की विरासत को अपने राजनीतिक खेमे में जोड़ने की कोशिश का है। उधर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी आकाश आनंद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। खास बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच पहले तल्लिखायं रही हैं। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आकाश बहुजन मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और दोनों साथ काम करेंगे।

लेकिन असली दिलचस्पी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रुख में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति में आने वाले



किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने मायावती पर भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का आरोप भी लगाया और कहा कि आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात की थी। यह बयान बताता है कि कांग्रेस भी इस घटनाक्रम को महज बहुजन समाज पार्टी का अंदरूनी मामला मानकर नहीं चल रही है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जवाब तो और भी सीधा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आकाश आनंद को समाजवादी पार्टी में जगह दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें उनके पास लाया जाता है तो वे उन्हें ले लेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला बहुजन समाज पार्टी का है और दूसरी पार्टियों के लोग उस पर कुछ नहीं कह सकते।

यहां सवाल उठता है कि आखिर आकाश आनंद को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? जबकि उत्तर प्रदेश के चुनावी आंकड़ों में छिपा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 22.23 प्रतिशत मत मिले थे और उसके 19 विधायक जीते थे। वर्ष 2022 में मत प्रतिशत घटकर 12.88 प्रतिशत रह गया और पार्टी महज एक सीट जीत सकी। लोकसभा चुनाव में भी तस्वीर बदली। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में पार्टी को करीब 19.43 प्रतिशत मत और 10 सीटें मिली थीं, जबकि वर्ष 2024 में मत प्रतिशत करीब 9.39 प्रतिशत रह गया और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी।

इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी का सामाजिक आधार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। खासकर जाटव समेत दलित मतदाताओं के एक हिस्से पर पार्टी का प्रभाव अभी भी उत्तर प्रदेश की चुनावी गणित में महत्वपूर्ण माना जाता

है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हर दल अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने के लिए संभावित रास्ते तलाश रहा है।

इस पूरी कवायद की जड़ में मायावती का 10 सितंबर का फैसला है। इससे पहले 3 सितंबर को आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक की अहम जिम्मेदारी से हटाया गया था। इसके बाद उनके ससुर और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की। इसके बावजूद मायावती ने आकाश को पार्टी से पूरी तरह मुक्त कर दिया। मायावती ने आकाश पर पार्टी और आंदोलन के मुकाबले पारिवारिक संबंधों को ज्यादा महत्व देने का आरोप लगाया और उनके रुख को लेकर सवाल उठाए।

दिलचस्प बात यह भी है कि आकाश आनंद का राजनीतिक सफर खुद उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। मायावती ने उन्हें दिसंबर 2023 में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां मिलीं, फिर हटाया गया, दोबारा जिम्मेदारी दी गई और फिर बाहर किया गया। अब एक बार फिर वे पार्टी से बाहर हैं। उधर, मायावती लगातार चुनावी गठबंधन से इंकार करती रही हैं। ऐसे में 2027 की लड़ाई में दूसरे दलों के सामने सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ सीधे तालमेल का रास्ता बंद है तो उसके सामाजिक आधार तक पहुंचने का रास्ता क्या हो? आकाश आनंद को लेकर दिखाई दे रही राजनीतिक हलचल शायद इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश है।

हालांकि यह आकलन भी चलेबाजी होगी कि किसी एक नेता के किसी दूसरे दल में जड़ जाने भर से पूरी पार्टी का सामाजिक आधार भी उसके साथ खिसक जाएगा। बसपा का कोर वोट बैंक आज भी बड़ी हद तक मायावती के साथ जुड़ा हुआ है और आकाश आनंद के पास अभी ऐसा कोई चुनावी नतीजा नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें मायावती के समान सामाजिक पकड़ वाला नेता माना जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने बसपा के लिए जमकर प्रचार किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे इलाकों तक उनकी सभाओं में भीड़ भी जुटी और वे पार्टी के प्रमुख प्रचारकों में शामिल रहे, लेकिन इसका चुनावी नतीजों में जरा भी असर नहीं दिखा।

अमेरिका की नई पैंतरेबाजी से डरने की जरूरत नहीं

ललित गर्ग

विश्व राजनीति में शक्ति केवल सैन्य क्षमता या आर्थिक आकार से निर्धारित नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि कोई महाशक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल किस प्रकार करती है। आज अमेरिका की व्यापार एवं प्रतिबंध नीति इसी कसौटी पर बहस के केंद्र में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका ने टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों को विदेश नीति के प्रमुख उपकरणों के रूप में अधिक आक्रामक ढंग से इस्तेमाल किया है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर संपावित सी प्रतिशत तक टैरिफ का अधिकार देने वाला नया अमेरिकी विधेयक इसी बदलते रुख का ताजा उदाहरण है, लेकिन इस नए बिल के जरिए वह भारत पर दबाव नहीं बना सकता। भारत को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई बन रही विश्व-संरचना में यह बिल अधिक प्रभाव नहीं बन सकेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को यह विधेयक पारित किया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि विधेयक राष्ट्रपति को ऐसा शुल्क लगाने का अधिकार देता है। भारत के संदर्भ में यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस भारत के ऊर्जा आयात का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। अगस्त 2026 में भारत रूस से लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात कर रहा था। ऐसे में यदि अमेरिकी राष्ट्रपति इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सीधा असर भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ सकता है और साथ ही भारत की ऊर्जा लागत भी दबाव बन सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। यहीं से असली सवाल उठता है-क्या व्यापारिक टैरिफ एक केवल व्यापार संतुलन सुधारने का साधन रह गए हैं या ये विदेश नीति को मनवाने का माध्यम भी बनते जा रहे हैं? अमेरिका और भारत के बीच व्यापार छोटा नहीं है। 2025 में दोनों देशों का वस्तु एवं सेवा व्यापार लगभग 239.6 अरब

डॉलर रहा और अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने भारत से 103.8 अरब डॉलर की वस्तुएं आयात कीं। इसलिए किसी बड़े अतिरिक्त टैरिफ का असर केवल भारत पर नहीं पड़ेगा, अमेरिकी आयातकों, उपभोक्ताओं और दोनों देशों की कंपनियों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए चुनौती दोहरी है। पहली चुनौती अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने की है और दूसरी ऊर्जा सुरक्षा की। यदि रूसी तेल पर निर्भरता अचानक घटानी पड़े तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में पहले से मौजूद अस्थिरता ऐसी स्थिति को और जटिल बना सकती है। दूसरी ओर अमेरिका को भी यह देखना होगा कि अत्यधिक टैरिफ से वैश्विक तेल आपूर्ति, कीमतों और अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मौजूदा कानून में राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय हित के आधार पर छूट की गुंजाइश भी रखी गई है। भारत की प्रतिक्रिया का महत्व यहीं बढ़ जाता है। भारत ने न तो किसी शक्ति-गुट के साथ अपने संबंध समाप्त करने की नीति अपनाई है और न ही अपने आर्थिक हितों को किसी एक देश की प्राथमिकताओं के अधीन करने की बात कही है। भारत का घोषित दृष्टिकोण ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना है। यही रणनीतिक स्वायत्तता बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बन सकती है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली में हाल में संपन्न 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखना उपयोगी होगा। भारत की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में 11 सदस्य देशों ने 140-बिंदु वाली नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया। ब्रिक्स ने सीमा-पार भुगतान को अधिक सुगम बनाने तथा सदस्य देशों की स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक निपटान की संभावनाओं पर आगे काम करने का समर्थन किया। साथ ही भारत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी साझा ब्रिक्स मुद्रा का प्रस्ताव नहीं है।

डीयू छात्रसंघ चुनाव में छत्तीसगढ़ का डंका, स्वतंत्र प्रत्याशी पीयूष जायसवाल ने 674 वोटों से दर्ज की जीत

गरियाबंद। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शहीद भगत सिंह संध्या कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव 2026 में स्वतंत्र प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के पीयूष जायसवाल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बेमेतरा के रहने वाले और देश के सबसे कम उम्र के मशहूर छात्र वैज्ञानिक व शोधकर्ता पीयूष जायसवाल ने किसी भी बड़े राजनैतिक दल का दामन थामे बिना, पूरी तरह स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर जॉइंट सेक्रेटरी (संयुक्त सचिव) पद पर एकतरफा चुनाव जीता है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को रिकॉर्डतोड़ 674 वोटों से हराकर विजय का परचम लहराया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ के किसी छात्र ने

बिना किसी पार्टी बैनर के सिर्फ अपने दम पर अपनी प्रेरक भाषण शैली और दमदार नेतृत्व के भरोसे इतनी बड़ी जीत दर्ज की हो।

पीयूष जायसवाल (सुपुत्रः प्यारे लाल जायसवाल, प्राचार्य डू डीएवी बेमेतरा) की यह अद्भुत प्रतिभा नई नहीं है, बल्कि इसकी नींव छत्तीसगढ़ में ही पड़ चुकी थी। पीयूष जब छत्तीसगढ़ के डीएवी देवभोग गरियाबंद में कक्षा 4थी से 7वीं तक की पढ़ाई कर रहे थे, तभी मात्र 12 वर्ष की कम में (कक्षा 7वीं के दौरान) उन्होंने एक नया कीर्तिमान रच दिया था। वे इतनी छोटी सी उम्र में ही लेखक, कवि, वैज्ञानिक और शोधकर्ता बनकर पूरी दुनिया को चौंका चुके थे। उन्होंने ब्रम्हांड के रहस्यों पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक और गति के नियमों



पर महत्वपूर्ण शोध पत्र लिखकर बचपन में ही देशभर में नाम रौशन कर दिया था।

मुख्य शासकीय एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सुसज्जित प्रोफाइल पीयूष

जायसवाल को उनकी असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ढेरों सम्मान मिल चुके हैं। इसी वर्ष 12 जनवरी 2026 को युवा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पीयूष को ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न’ पुरस्कार और 2,50,000 (ढाई लाख रुपये) की प्रोत्साहन राशि से विशेष रूप से सम्मानित किया था। भौतिकी और खगोल विज्ञान की इतनी जटिल गणनाओं को इतनी कम उम्र में हल करने के कारण इन्होंने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के पुराने कीर्तिमानों को चुनौती दी। सबसे कम उम्र में विज्ञान अनुसंधान के लिए इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसके अलावा उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) अवार्ड, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार चेन्नई दिल्ली में, बाल श्रेष्ठ पुरस्कार दिल्ली और समाज की ओर से कलचुरी गौरव रत्न पुरकार दिल्ली सहित 75 से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय

व प्रांतीय सम्मान मिल चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पीयूष जायसवाल के पास न तो कोई बड़ा राजनैतिक सहयोग था और न ही कोई बड़ी पार्टी का नाम। उन्होंने केवल अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता, बेबाक भाषण शैली और छात्र कल्याण के विजन को आगे रखा। जब पीयूष कॉलेज परिसर में भाषण देते थे, तो दिल्ली के स्थानीय छात्रों से लेकर अन्य राज्यों के छात्र उनकी वैज्ञानिक सोच और नेतृत्व क्षमता के मुरीद हो जाते थे। परिणाम यह रहा कि छात्रों ने पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठकर पीयूष को एकतरफा वोट देकर जिताया इस खबर से पूरे छत्तीसगढ़ में जशन का माहौल है, लोग पीयूष जायसवाल को बधाई व शुभकामनाएं दे रहे।



पागल कुत्ते का आतंक: 31 लोगों को काटकर किया घायल,

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आगरा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच एक आक्रामक कुत्ते ने 31 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल, वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 और 4 में कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुत्ता एक दिन पहले से असामान्य व्यवहार कर रहा था और राह चलते लोगों को निशाना बना रहा था। अब तक उसने 31 लोगों को घायल कर दिया है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। अस्पताल के डॉ. नरेंद्र रात्रे ऋछू ने बताया कि सभी 31 घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया है और उनकी हालत सामान्य है। इधर, पार्षद रामनाथ सिदार ने प्रशासन से तत्काल कुत्ते को पकड़ने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी घटना हो सकती है। नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंचकर कुत्ते को पकड़ने के प्रयास में जुटी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इधर बच्चे पर हुए कुत्ते के हमला का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से आक्रामक कुत्ता अचानक बच्चे के पास पहुंचा और उसे बुरी तरह से नोंच डाला।

यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी, 20 घायल

बालोद। बालोद में बेलगाम रफ्तार दर्दनाक सड़क हादसे का कारण बन गई। यात्रियों से भरी बस करहीभदर के पास दुर्घटना का शिकार हो गई। एक युवक की मौत हो गई है। वहीं 20 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, हादसे का शिकार हुई बस डीआरडी की बताई जा रही है। बड़ी संख्या में आम यात्री सवार थे। शनिवार सुबह बस बालोद से धमतरी की ओर जा रही थी। इसी दौरान करहीभदर के पास बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हादसे के बाद शव को बस से बाहर निकालने में भी काफी मशक़त करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि शव को बाहर निकालने में करीब एक घंटे का समय लगा। वहीं घायलों को तत्काल एंबुलेंस 108 की मदद से बालोद जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। फिलहाल हादसे की सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले को जांच में जुटी हुई है।

कबीरधाम पुलिस का एक्शन: 40 आबकारी केस दर्ज

कवर्धा।कबीरधाम जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और अवैध रूप से शराब पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक ही रात में बड़ी कार्रवाई की है। 18 सितंबर को पुलिस ने एक्शन लेते हुए जिले के अलग-अलग थाना इलाकों में 40 केस दर्ज किए हैं। 40 प्रकरणों में से सिटी कोतवाली थाना इलाके में ही एक रात में 30 आबकारी प्रकरण दर्ज किए। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के साथ ही अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले शामिल हैं। रायपुर रोड, नया बस स्टैंड, छिहरा रोड, राजनांदगांव रोड, समनापुर और ट्रांसपोर्ट नगर जैसे कई जगहों पर ये कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में हुई है। जिसमें सरोधा डैम के पास लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में कमलेश साहू के खिलाफ धारा 36(सी) के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते मिले 29 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 36(च)(1) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए

प्राचार्या वंदिनी श्रीवास्तव को पद से हटाया गया

बलौदाबाजार। शहर के पंडित चक्रपाणी शुक्ल उत्कृष्ट विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या को पद से हटा दिया गया है। छात्र-छात्राओं से कथित अभद्र व्यवहार, शिक्षक के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने की शिकायत और पत्रकारों से हुए विवाद के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी प्राचार्या वंदिनी श्रीवास्तव को हटाकर वरिष्ठ व्याख्याता निर्मला साहू को विद्यालय का अस्थायी प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रभार सौंपा गया है। स्कूल में शराब सेवन कर आने और छात्र-छात्राओं के साथ कथित गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार के आरोपों से घिरे व्याख्याता नरेश तिवारी के मामले में भी शिक्षा विभाग ने निलंबन की अनुशंसा की है। जिला शिक्षा अधिकाी कार्यालय की ओर से निलंबन का प्रस्ताव शिक्षा संचालनालय, रायपुर भेजा गया है। यह कार्रवाई 18 सितंबर 2026 को जारी आदेश के बाद सामने आई है। पिछले कई दिनों से विवादों में रहे इस विद्यालय में शिक्षा विभाग की कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। व्याख्याता के शराब पीकर पहुंचने के मामले में कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से हुआ था।

जशपुर की पहचान रानीसती तालाब का होगा जीर्णोद्धार

जशपुर।जशपुर शहर के हृदय स्थल में स्थित रानीसती उद्यान तालाब और पार्क का करोड़ों की लागत से जीर्णोद्धार होगा।इस तालाब और पार्क को नया स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार ने 4.117 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की स्वीकृति के बाद नगर पालिका परिषद ने निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। छठ पूजा के बाद तालाब के जीर्णोद्धार का काम शुरू किए जाने की तैयारी है। सती उद्यान तालाब को शहर में डोंगा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस तालाब की लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण इसमें जलीय खरपतवार का फैलाव हो गया है।इससे तालाब की जलधारण क्षमता प्रभावित होने के साथ इसका स्वरूप भी बिगड़ गया है। शहरवासियों की लगातार मांग को देखते हुए नगर पालिका ने तालाब के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा था ।

डीएपी, एनपीके खाद की कमी से फसल को हो सकता है ख़तरा!

कोरबा सरकार के तमाम दावों के विपरीत कोरबा जिले में खाद की किल्लत बनी हुई है. कृषि विभाग के अपने ही आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं. जिले के किसानों को डीएपी (छक्का) और एनपीके (हक्का) जैसे महत्वपूर्ण उर्वरक समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. हालात यह हैं कि विभाग तय किए गए लक्ष्य का आधा भंडारण भी नहीं कर पाया है, जिसके चलते किसानों को ज़रूरत से काफी कम मात्रा में खाद का वितरण हो सका है. खाद के काम भंडारण और वितरण संबंधी जानकारी कृषि विभाग ने हाल ही में संपन्न हुई जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में पेश किए थे.कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के खरीफ़ सीजन के लिए कोरबा जिले के किसानों को कुल 1,500 मीट्रिक टन एनपीके खाद बांटा जाना था. इसके विपरीत, अभी तक महज 877 मीट्रिक टन एनपीके खाद ही किसानों तक पहुंच पाया है. जिससे ऐतं बुवाई और फसल के शुरुआती दौर में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विस्थापन पर बवाल : 36 परिवारों ने कलेक्टर से लगाई गुहार

गरियाबंद। जिले के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। अभ्यारण्य प्रशासन पर विस्थापन के लिए ग्रामीणों को उकसाने का आरोप लगा है। गांव में 36 परिवार का एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर रणवीर शर्मा से भेंटकर जापन सौंपकर अपनी मांग रख दी है, हालांकि कलेक्टर ने इस मसले पर 21 तारीख को जिला स्तरीय समन्वय बैठक में लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर कार्रवाई तय करने का भरोसा दिलाया है।

दरअसल, 17 सितम्बर को अभ्यारण्य उपनिदेशक के साथ कलेक्टर ने गांव पहुंचकर विस्थापन को लेकर बैठक किया, जिसमें गांव का एक छोटा समूह शामिल हुआ। बड़े समूह और स्थानीय आदिवासी नेताओं की मांग है कि पूरी प्रक्रिया पेशा कानून के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत हो,



गांव में मौजूद सैकड़ों एकड़ भूमि की वैधानिक स्थिति से लेकर विस्थापन से जुड़ी सभी नियम शर्तों को सार्जनिक किया जाना चाहिए। ग्रामीणों को दलील है कि ऐसा नहीं हुआ, तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम ने कहा कि ग्राम देवझरअमली में लगभग 156 परिवार निवासरत हैं, जिनमें 36 परिवारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपने पुरखों की जगह और जल-जंगल-जमीन छोड़कर नहीं जाना चाहते। यह गांव केवल रखने की जगह नहीं, बल्कि ग्रामीणों की पीढ़ियों पुरानी सामाजिक, सांस्कृतिक

और धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण लंबे समय से गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, संचार और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग करते रहे हैं, लेकिन जब गांव में विकास की बात आती है तो अनेक प्रकार की विभागीय अड़चनं सामने आती हैं और दूसरी ओर विस्थापन के लिए परिवारों को भूमि एवं आर्थिक पैकेज की बातें बताई जा रही हैं। एक तरफ गांव में विकास के लिए बजट और सुविधाओं की कमी बताई जाती है और दूसरी तरफ विस्थापन के नाम पर करोड़ों रुपये के पैकेज की बातें सामने आती हैं, यह स्थिति ग्रामीणों के लिए गंभीर सवाल खड़ा करती है। यह क्षेत्र सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र नहीं है बल्कि ऋक्ष और वन अधिकार अधिनियम (स्नक्र) जैसे कानूनों के तहत ग्राम सभा की महत्वपूर्ण वैधानिक भूमिका है। स्नक्र के तहत ग्राम

देवझरामली को लगभग 768.55 हेक्टेयर सामुदायिक वन संसाधन (छस्नक्र) अधिकार प्राप्त है। ऐसे में यदि विस्थापन की बात की जा रही है तो प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि मान्य सामुदायिक वन अधिकारों और ग्रामीणों के अन्य वन अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित होगी। जनप्रतिनिधियों की दलील है कि यदि प्रशासन या वन विभाग विस्थापन को आवश्यक मानता है, तो उसका विधिक आधार, संबंधित दस्तावेज, पुनर्वास पैकेज, अधिकारों की स्थिति तथा कानून में निर्धारित प्रक्रिया ग्राम सभा और प्रभावित परिवारों के समक्ष स्पष्ट रूप से रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण का विरोध ग्रामीण नहीं कर रहे हैं, बल्कि संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच कानून सम्मत एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं।

गड्डों से पटे पड़े सड़क पर दीए जलाकर किया अनोखा प्रदर्शन

धमतरी। जिले की बदहाल सड़कों की वजह से आम जनता को ही रही परेशानी के विरोध में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने अनोखा प्रदर्शन किया। सेना के कार्यकर्ताओं ने सिहावा रोड पर दीया जलाकर विरोध जताया।

इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह प्रदर्शन सड़क पर दीया जलाकर हस्रिए किया गया है, क्योंकि जिले की सड़कें गड्डों से भर चुकी है। यह समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क।

हर रोज इन गड्डों की वजह से दुर्घटना हो रही है। बात की जाए सिहावा रोड की तो इस रोड से जब भी कोई बड़ी वाहन सड़क से गुजरती है, तो दो पहिया वाहन सवार बिल्कुल भी नजर नहीं



आता, वह धूल में समा जाता है। जो भी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन कर निकलता है, वह धूल से नहा लेता है। धमतरी शहर के सभी सड़कों का यही हाल है।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिम्मेदार केवल बारिश के बाद सड़क बनाए जाने की बात कहते हैं, लेकिन सड़क में गिट्टी डालकर उसे और बर्बाद करने का कार्य जिम्मेदार अधिकारी और

जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। इससे आम जनता केवल परेशान हो रही है।

सड़क पर उड़ने वाले धूल के गुब्बारे से खंभे में लगी लाइट भी दिखाई नहीं देती, इसलिए सड़क में हाथों में दीए जलाकर सोए हुए अधिकारी और नेताओं को जगाने के साथ इस धूल में सने हुए अंधेरे को उजाले में तब्दील करने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है।

स्वस्थ नागरिक, समृद्ध छत्तीसगढ़

हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़

राज्य सरकार की दूरदृष्टि, अपार वन संपदा और आयुर्वेदिक पारंपरिक ज्ञान के बल पर छत्तीसगढ़ हर्बल प्रसंस्करण इकाइयों का नया हब बन रहा है। 27.87 एकड़ में अत्याधुनिक हर्बल सेंटर, रोजगार सृजन और किसानों की आय वृद्धि के साथ राज्य को नई आर्थिक पहचान मिल रही है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़, भारत में हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। राज्य सरकार आयुर्वेद, हर्बल और वेलनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियों, अत्याधुनिक अवसंरचना और निरंतर निवेश के माध्यम से एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रही है। राज्य की अपार वन संपदा, पारंपरिक ज्ञान और किसानों की सक्रिय भागीदारी से यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है।



प्रसंस्करण इकाइयों की प्रभावी विशेषताएं

- 27.87 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक हर्बल प्रसंस्करण इकाई।
- 36.47 एकोड़ रुपये की लागत से निर्माण।
- यूएसएफडीए (USFDA) मानक तकनीक से युक्त।
- रोजाना 400 से अधिक प्रकार की जड़ी-बूटियों की प्रोसेसिंग क्षमता।
- हर्बल चाय, कैप्सूल, पाउडर, एक्सट्रेक्ट, तेल और अन्य मुल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण।

जड़ी-बूटियों की अपार वन संपदा

छत्तीसगढ़ की विविध जलवायु, समृद्ध वन क्षेत्र और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ इसे औषधीय पौधों की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में स्थान दिलाती हैं। राज्य के जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों में अशोक, शतावरी, कालमेघ, गिलोय, सफेद मुसली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं।

- ये जड़ी-बूटियाँ केवल आयुर्वेद और पारंपरिक उपचार पद्धतियों में ही उपयोगी नहीं हैं, बल्कि हर्बल उद्योग, औषधि निर्माण और स्वास्थ्य उत्पादों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन हैं।
- राज्य सरकार जड़ी-बूटियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ वनवासियों समुदायों को आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है।

सरकार की नीतियों और समर्थन

- हर्बल उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति और वित्तीय प्रोत्साहन।
- किसानों को जड़ी-बूटी की खेती के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बीज उपलब्धता।
- किसान उत्पादक संगठनों (FPOS) और स्व सहायता समूहों को हर्बल वैल्यू चेन से जोड़ना।
- अनुसंधान एवं विकास के लिए संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग।
- जड़ी-बूटियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष अभियान।

रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति



यह इकाई सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से 2,000 से अधिक लोगों को रोजगार देगी।



स्थानीय किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।



हर्बल उद्योगों से जुड़े स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।



युवाओं के लिए कौशल विकास और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के नए अवसर उपलब्ध होंगे।



आयुर्वेद और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा

- छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद और वेलनेस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं।
- योग, पंचकर्म, आयुर्वेदिक चिकित्सा और हर्बल थेरेपी के क्षेत्र में राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना।
- स्थानीय हर्बल उत्पादों को वेलनेस रिसॉर्ट्स, आयुर्वेदिक केंद्रों और पर्यटन स्थलों से जोड़ना।
- आयुर्वेदिक शिक्षा, शोध और इनोवेशन के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहचान बनाना।

लोक विकास से लोक वैज्ञानिक क्रांति तक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लोक विकास की दिशा में अग्रसर है। हर्बल और आयुर्वेदिक क्षेत्र में यह पहल राज्य को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



गुणवत्ता और नवाचार पर विशेष ध्यान

छत्तीसगढ़ में हर्बल एवं आयुर्वेदिक क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में जड़ी-बूटियों की गुणवत्ता, शुद्धता, औषधीय गुणों तथा उत्पादों की प्रभावशीलता की वैज्ञानिक जांच की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सकें।



छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा और पारंपरिक ज्ञान आज जड़ी-बूटियों के माध्यम से नई पहचान प्राप्त कर रहा है। राज्य के वन क्षेत्रों में उपलब्ध औषधीय पौधे न केवल स्वास्थ्य संवर्धन का आधार बन रहे हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रहे हैं। जड़ी-बूटियों के संरक्षण, वैज्ञानिक उपयोग और प्रसंस्करण के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदा को आर्थिक शक्ति में बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे किसानों, वनवासियों और महिला स्व-सहायता समूहों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।



अशोक

महिलाओं के स्वास्थ्य और हार्मोन संतुलन में सहायक।



शतावरी

शक्ति व स्टेमिना बढ़ाने, हार्मोनल बैलेंस के लिए लाभकारी।



कालमेघ

लिवर की सेहत, प्रतिरक्षा बढ़ाने और बुखार में उपयोगी।



गिलोय

इम्युनिटी बढ़ाने, डायबिटीज और बुखार में लाभकारी।



जंगली हल्दी

त्वचा की देखभाल, सौंदर्य प्रसाधन और आयुर्वेदिक उपचारों के लिए गुणकारी।



बहेड़ा

गले के रोग, खाँसी और पाचन विकारों में लाभकारी।



आंवला

विटामिन सी से भरपूर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला।



सफेद मुसली

ऊर्जा, शक्ति और शारीरिक कमजोरी दूर करने में सहायक।

छत्तीसगढ़ की ये जड़ी-बूटियाँ स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक समृद्धि का भी आधार बनेंगी।

पर्यावरण संरक्षण को बल



जड़ी-बूटियों की खेती और संरक्षण से वनों का संरक्षण होगा और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहेगा।

वैश्विक बाजार में पहचान



हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग से छत्तीसगढ़ के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाएंगे।

स्वस्थ समाज, समृद्ध राज्य



आयुर्वेद और हर्बल उत्पादों के प्रचार-प्रसार से समाज स्वस्थ होगा और राज्य की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी।

किसानों की समृद्धि



जड़ी-बूटी की खेती से किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

भविष्य की दिशा



छत्तीसगढ़ को हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों का वैश्विक हब बनाना हमारा संकल्प है।

छत्तीसगढ़ - हर्बल हब, आयुर्वेद की नई पहचान

औद्योगिक नीति 2024-30 से प्रदेश में निवेश और रोजगार को नई गति

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अंबिकापुर में आयोजित दो दिवसीय ‘अग्र महाकुंभ-2026’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अग्रवाल समाज की उद्यमिता, दानशीलता, परोपकार और समाजसेवा की समृद्ध परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अग्रवाल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यापार और व्यवसाय से आगे बढ़कर समाज के उद्यमियों ने उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और जनसेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक समानता, करुणा, सहयोग और सहभागिता पर आधारित समाज की कल्पना की थी। उनका संदेश था कि समाज की वास्तविक उन्नति तभी संभव है,

मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान, सभी 33 जिलों में स्थापित होंगे उद्यमिता विकास केंद्र

जब प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले और जो सक्षम हैं, वे जरूरतमंद लोगों का हाथ थामकर उन्हें भी प्रगति की राह पर आगे बढ़ाएं। अग्रवाल समाज ने महाराजा अग्रसेन जी के इन आदर्शों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने आचरण में उतारा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अग्रवाल समाज की पहचान केवल सफल व्यापार और उद्यमिता तक सीमित नहीं है। अर्थोपाजन के साथ परमार्थ की भावना इस समाज की विशिष्टता रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों, धर्मशालाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं तथा अनेक जनसेवा गतिविधियों के माध्यम से समाज निरंतर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाता आया है।

कोरोना महामारी के कठिन समय का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरा देश अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा था, तब अग्रवाल समाज ने आगे बढ़कर जरूरतमंदों की सहायता की।

महिला शक्ति और युवाओं की भागीदारी से समाज को मिलेगी नई ऊर्जा

मुख्यमंत्री श्री साय ने अग्र महाकुंभ में महिला शक्ति को विशेष स्थान दिए जाने की सराहना करते हुए कहा कि आज हमारी बेटियां और बहनें परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के साथ व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, स्टार्टअप और समाजसेवा सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रही हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी परिवार, समाज और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई शक्ति प्रदान कर रही है। उन्होंने युवाओं के लिए आयोजित विशेष सत्र को भी महत्वपूर्ण बताया हुआ कि बदलते समय में नई पीढ़ी के सामने अवसरों का एक विशाल संसार है।

मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाना हो अथवा स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों की मदद करना हो, समाज ने सेवाभाव का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में ऐसा सुरक्षित, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जहां व्यापार और उद्योगों का विस्तार हो, निवेश बढ़े और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित हों। उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े अग्रवाल समाज के अनुभवी लोगों के सुझाव शासन की नीतियों को और अधिक व्यावहारिक एवं जनोपयोगी बनाने में सहायक रहे हैं।

चित्रों में उकेरे सपनों का भारत, भाषण में गूंजी विकसित भारत की कल्पना

सेवा संकल्प अभियान : 2447 स्कूलों के बच्चों ने संकुल स्तर पर दिखाई प्रतिभा



बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के 2,447 स्कूलों में आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए आज संकुल स्तर पर चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संकुल स्तर की प्रतियोगिता में खंड हजार से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने चित्रों और अपने विचारों के माध्यम से भारत की उपलब्धियों, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के सपनों को जीवंत रूप दिया।

प्रतियोगिता दो श्रेणियों में आयोजित की गई। प्रथम श्रेणी में विगत 25 वर्षों की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। इसमें स्वच्छ भारत,

डिजिटल इंडिया, सेना का शौर्य, नया कश्मीर और नक्सलवाद जैसे विषयों पर बच्चों ने चित्र बनाए और भाषण प्रस्तुत किए। चित्रकला में बच्चों ने अपने रचनात्मक कौशल के माध्यम से इन विषयों को प्रभावी ढंग से उकेरा, वहीं भाषण के माध्यम से उन्होंने बीते 25 वर्षों की उपलब्धियों और चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त किए।

द्वितीय श्रेणी आगामी 25 वर्षों के ‘सपनों के भारत’ पर केंद्रित रही। इसमें सपनों का भारत, विकसित भारत 2047, नक्सल मुक्त भारत, महिला सशक्तिकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रभाव जैसे विषय शामिल किए गए। बच्चों ने चित्रों और भाषणों के माध्यम से विकसित

स्मार्ट फोन व स्मार्ट केन से ललिता के जीवन में आया बदलाव

शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनके जीवन को आसान बनाने का जरिया बन रही है। ऐसे ही बदलाव की कहानी शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय तिफरा में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत कुमारी ललिता यादव की है। समाज कल्याण विभाग द्वारा ललिता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत स्मार्ट फोन एवं स्मार्ट पेन (छड़ी) का लाभ मिला। इन सुविधाओं ने उनकी पढ़ाई के साथ-साथ आवागमन को भी आसान बनाया है। पहले की स्थिति में विषय-वस्तु से संबंधित ऑडियो एवं वीडियो सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण ललिता को अध्ययन में कठिनाई होती थी। आवश्यक अध्ययन सामग्री तक सीमित पहुंच के कारण विषयों को समझने और सीखने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता था। वहीं आवागमन के दौरान भी उन्हें सुविधा की आवश्यकता महसूस होती थी। अब की स्थिति में स्मार्ट फोन उनके अध्ययन का महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

श्वेता नायक एंड ग्रुप ने कुचिपुड़ी नृत्य से मोहा दर्शकों का मन



‘शिवशक्ति समर्पण’ में दिखा भगवान शिव के तांडव और माता पार्वती के लास्य का दिव्य संगम

रायपुर। 41वें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह की सांस्कृतिक संध्या में बिलासपुर की श्वेता नायक एंड ग्रुप ने कुचिपुड़ी नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ‘शिवशक्ति समर्पण’ शीर्षक से प्रस्तुत इस नृत्य में भगवान शिव के तांडव और माता पार्वती के लास्य का मनोहारी संगम देखने को

मिला। प्रस्तुति में भक्ति, शक्ति, सौंदर्य और लय का सुंदर समावेश रहा। कार्यक्रम का आरंभ ‘मोनाक्षी पंचरत्नम्’ से हुआ। रागमालिका और आदि ताल में प्रस्तुत इस रचना के माध्यम से देवी मोनाक्षी के दिव्य स्वरूप, सौंदर्य और महिमा को कुचिपुड़ी की भावपूर्ण अभिव्यक्ति में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद ‘तरंगम’ की प्रस्तुति ने दर्शकों का विशेष आकर्षण खींचा। थाली पर संतुलित नृत्य, जटिल पदसंचालन, लय और भाव के अद्भुत समन्वय ने प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया। ‘शिवशक्ति समर्पण’ में भगवान शिव के गंगाधर, चंद्रचूड़ और आनंद नटराज स्वरूपों का भावपूर्ण निरूपण किया गया। गंगा के शिव की जटाओं में अवतरण और भगवान शिव द्वारा लोककल्याण के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के प्रसंग को नृत्य के माध्यम से जीवंत किया गया। गुरु श्वेता नायक के निर्देशन में जी. धारणी, श्री दिप्ता पॉल, चेतन्या साहू, मेघा सारथी, ऐश्वर्या, श्वेता सालिनी नायक, एन. स्तुति रेड्डी, एन. दिव्यांका, हर्षिता केवत सहित कलाकारों ने प्रस्तुति दी।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

बनोरा अघोर गुरु पीठ पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। परम पुज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिले के ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरु पीठ पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय ने उपसना स्थल पर अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के दर्शन कर श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने आश्रम की परंपरा के अनुरूप सादगी के साथ पंगत में बैठकर प्रार्थना ग्रहण किया। इस दौरान आश्रम का सहज, सेवाभावी और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री साय इसके पश्चात अघोरेश्वर भगवान राम विद्या मंदिर के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नवीन विद्यालय भवन का लोकार्पण कर विद्यालय परिवार, विद्यार्थियों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर का अवलोकन किया और विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी भी देखी।

झीरम कांड की सच उजागर करने सर्व आदिवासी समाज की पुनर्जांच की मांग का आम आदमी पार्टी

रायपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता बल्लू राम भवानी ने 25 मई 2013 के भीषण झीरम घाटी कांड को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा एनआईए कोर्ट के फैसले को बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती देने और पूरे षड्यंत्र की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। बल्लू राम भवानी ने कहा कि 13 साल बीत जाने के बाद भी घटना के पीछे की राजनीतिक व आपराधिक साजिश का बेनकाब न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। झीरम घाटी कांड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और सुरक्षाकर्मियों समेत दर्जनों लोगों की हत्या हुई थी। लेकिन सालों की जांच के बाद भी केवल निचली सतह के लोगों या कथित निर्दोष आदिवासियों को मोहरा बनाकर मुख्य साजिशकर्ताओं को छोड़ दिया गया। सर्व आदिवासी समाज की बैठक में उठे मुद्दों—जैसे कि 10 स्थानीय ग्रामीणों को गलत तरीके से फंसाया जाना और आत्मसमर्पित नक्सलियों को दिए गए लाभों के पुनर्मूल्यांकन की मांग बिल्कुल जायज है।

नन्हे दिल को मिली नई धड़कन

रायपुर। समय पर ली गई एक सही स्वास्थ्य जांच किसी मामूमी का पूरा भविष्य संवार सकती है, इसका जीवंत उदाहरण धमतरी के नन्हें भाव्यांश साहू की यह सफलता की कहानी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत संचालित चिरायु योजना ने जन्मजात हृदयरोग से जूझ रहे इस बच्चे को न केवल समय पर सही इलाज दिलाया, बल्कि उसके परिवार के जीवन में खुशियों की एक नई रोशनी भी बिखेर दी। कहानी की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई, जब शहरी चिरायु टीम धमतरी ने जालमपुर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक-01 में बच्चों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण किया। जांच के दौरान डॉक्टरों की सजग नजरों ने भाव्यांश में जन्मजात हृदयरोग के लक्षणों को तुरंत पहचान लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टीम ने बिना कोई समय गंवाए बच्चे को आगे के उच्च स्तरीय उपचार के लिए श्री सत्य साई अस्पताल, नया रायपुर रेफर किया और पूरे मार्गदर्शन तथा सहयोग के साथ परिजनों की हिम्मत बढ़ाई। अस्पताल में विशेषज्ञों की गहन जांच और परामर्श के बाद सर्जरी का निर्णय लिया गया।

सौर ऊर्जा से रोशन हुआ किसान नेतराम का घर

रायपुर। प्रदेश में "सेवा संकल्प अभियान" के माध्यम से जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से न केवल आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है। ऐसा ही एक प्रेरक उदाहरण सारंगढ़-बिलासगढ़ जिले के ग्राम गोबरसिंहा निवासी किसान नेतराम पटेल का है, जिनके जीवन में श्रध्दानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाश्र आर्थिक संबल बनकर उभरी है। योजना का लाभ लेने से पहले नेतराम पटेल के घर का मासिक बिजली बिल करीब 2,200 से 2,300 रुपए तक आता था, जो उनके बजट पर एक बड़ा वित्तीय बोझ था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत पर सौर पैनल (रूफटॉप सोलर सिस्टम) स्थापित होने के बाद अब उनका मासिक बिजली बिल घटकर मात्र 250 से 300 रुपए रह गया है। सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की जरूरतें घर पर ही पूरी होने से नेतराम को हर महीने लगभग 2,000 रुपए की सीधी बचत हो रही है। इस बचत राशि का उपयोग वे अपनी खेती-किसानी से जुड़े दैनिक खर्चों को पूरा करने में कर रहे हैं।

बस अनियंत्रित होकर पलटी एक की मौत, 20 से घायल

बालोद। शनिवार की सुबह करहीभदर के पास कर्मचारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। युवक के शव को बाहर निकालने में करीब एक घंटा लग गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि दुर्घटना वास्तव में किन परिस्थितियों में हुई, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शनिवार सुबह बालोद से धमतरी की ओर जा रही डीआरडी की बस करहीभदर के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से अधिक सवारी सवार थे और अचानक बस चालक बस पर नियंत्रण नहीं कर पाया और वह पलटकर सीधे खेत के नीचे उतर गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों की मदद की और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू किया।

‘सपनों का भारत-विकसित भारत’ की संकल्पना को किया साकार

सेवा संकल्प : विद्यार्थियों ने लिया स्वच्छता का संकल्प

बिलासपुर। सेवा संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत आज लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में विद्यार्थियों की सहभागिता से सपनों का भारत-विकसित भारत की संकल्पना को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 300 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुम्हार शामिल हुए।

इस अवसर पर विद्यार्थियों ने स्वच्छता की शपथ लेते हुए अपने विद्यालय, घर, आसपास के क्षेत्र एवं शहर को स्वच्छ रखने तथा

स्वच्छता के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों को बताया गया कि विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति से ही नहीं, बल्कि स्वच्छ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से संभव होगा। कार्यक्रम में बच्चों को स्वच्छता को केवल अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे अपने दैनिक जीवन की आदत बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें अपने घर और विद्यालय के साथ-साथ आसपास के सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने तथा परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया। बच्चों को बताया गया कि आज के विद्यार्थी

ही कल के भारत का भविष्य हैं। उनके विचार, व्यवहार और जिम्मेदारियां देश के भविष्य की दिशा तय करेंगी। स्वच्छता, अनुशासन, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे संस्कारों को अपनाकर विद्यार्थी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में जनसेवा, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता ने यह संदेश दिया कि स्वच्छता का संकल्प-विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के झीरम नक्सली हमले के मामले में एनआईए की विशेष न्यायलय ने कुल 39 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 10 आरोपियों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। वहीं फैसले में 27 नक्सलियों का भी उल्लेख है, जिन्हें फरार बताया गया है। इनमें कुछ के आत्मसमर्पण करने अथवा मुठभेड़ में मारे जाने का भी उल्लेख है। मामले में फरार घोषित किए गए 27 आरोपी नक्सलियों को लेकर वर्तमान में स्थिति बदल गई है। फरार आरोपियों में से 14 के आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने एवं 09 के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अब तक फरार 04 नक्सली ऐसे हैं, जिनकी

तलाश जारी है। एनआईए की विशेष न्यायलय ने मामले के आरोपित 14 आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को भी फरार बताया गया है। झीरम नक्सली हमले मामले में एनआईए न्यायलय द्वारा नामजद फरार घोषित किए गए 27 आरोपी नक्सलियों के नाम - सोमा सोढ़ी उर्फ सुन्दर उर्फ सुरिन्दर, बारसे सुक्का उर्फ देवा उर्फ देवना, सणो हुंगा उर्फ विनोद, कुम्मे

मोडियाम, पाका हनुमंथ उर्फ गणेश उईके, वैगुला अरूणा उर्फ माधवी उर्फ माधवका, मोडियम रमेश उर्फ लच्छु, तेलाम आयतु उर्फ आयतु डोड़ी, गीता पुनेम उर्फ गीता पोटा, मंगली कोसा, मड्डु मड़ुकासी, सतु वैट्टी, भात हेमला उर्फ बदरू, कामेश कवासी, कोरसा सत्री उर्फ सत्री कोरसाम, कोरसा सतु, सोमी पोटराम उर्फ सोनी पोटराम, कुरसाम सत्री उर्फ कोसी उर्फ लच्छी, लक्खू पुनेम उर्फ गंगा पुनेम, कोरसा लक्खू, बदरू मोडियाम उर्फ मांतु, सरिता काकेम उर्फ मिटकी, कुम्मा गोंदे उर्फ गुड्डु, हेमला मासा उर्फ संजय कवासी बदरू उर्फ सुखराम उर्फ गद्दाम बदरू, जयलाल मंडावी, एवं शीर्ष नक्सली कैडर तिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी शामिल हैं।